सर्वहारा दृष्टिकोण

सोशलिस्ट यूनिटी सेन्टर ऑफ इण्डिया (कम्युनिस्ट) का मुखपत्र (पाक्षिक)

वर्ष-26 अंक-20 22 अक्टूबर से 5 नवम्बर, 2011 मुख्य संपादक - कॉमरेड कृष्ण चक्रवर्ती मूल्य : 2 रुपये

महान नवम्बर क्रांति की यादगार सीख और सार्थकता

दुनिया के तमाम देशों में पूँजीवाद-साम्राज्यवाद के निर्मम शोषण से त्रस्त मेहनतकश अवाम की मुक्ति की जो महती ऐतिहासिक जिम्मेवारी इतिहास ने इस युग के सच्चे कम्युनिस्टों के कंधों पर सौंपी है, हर साल नवम्बर क्रांति दिवस हमें उस जिम्मेवारी की याद दिला देता है। दुनिया भर के कम्युनिस्टों के लिए यह खास दिवस मनाना महज रस्म अदायगी नहीं है। यह दिन आने वाले दिनों के क्रांतिकारी आंदोलन की जरूरत से अतीत के क्रांतिकारी आंदोलन के तजुर्बों की गहन समीक्षा कर उससे सीख लेने का दिन है। 1917 की महान नवम्बर क्रांति, जिसने विश्व पूँजीवाद के चक्रव्यूह को तोड़कर रूस में दुनिया के पहले समाजवादी राज्य की स्थापना की थी, एक युगांतकारी घटना थी। लेकिन यह घटना अचानक नहीं घटी थी। क्रांतिकारी सिद्धांत को वास्तव में किस तरह से प्रयोग में लाया जाता है, उसी की एक जीती-जागती मिसाल है नवम्बर क्रांति। मानव-समाज की प्रगति को बाधित करने वाली शोषणमूलक पूँजीवादी व्यवस्था की जंजीरों को तोड़कर इस क्रांति ने हर मामले में पिछड़े हुए रूस को पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। विभिन्न देशों में सर्वहारा क्रांतिकारी आंदोलन को सफल बनाने के लिए हमें महान नवम्बर क्रांति से सीख लेनी ही होगी।

महान क्रांतिकारी दार्शनिक कार्ल मार्क्स ने ही सबसे पहले समाज-विकास के वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर पूँजीवादी व्यवस्था के खात्मे और समाजवादी व्यवस्था की स्थापना के अवश्यम्भावी होने का एलान किया था। उन्होंने ही सबसे पहले दिखाया था कि सर्वहारा वर्ग को लामबंद कर पूँजीवादी शोषण के खिलाफ संघर्ष में उतरने की जमीन खुद बुर्जुआ समाज ही तैयार कर देता है और इसलिए दो परस्पर विरोधी वर्गों के बीच जारी वर्ग-संघर्ष के तेज होने से सामाजिक क्रांति के जरिये पहले समाजवाद और बाद में साम्यवाद की ओर मानव-समाज अनिवार्य रूप से अग्रसर होता है। जब तक अनियंत्रित उत्पादन व्यवस्था और वस्तुजगत व भावजगत में व्यक्तिगत मालिकाना मौजूद रहेगा, तब तक यह वर्ग-संघर्ष जारी रहेगा। पूँजीवादी समाज के विकास के साथ-साथ सर्वहारा वर्ग के आविर्भाव की घटना को समाज के 'कोढ़' के रूप में न देख कर मार्क्स ने ही सबसे पहले कहा था कि इसके चलते समाज अपने मुख्य द्वन्द्व से मुक्त होगा। समाज-विकास की इस धारा को चिह्नित कर द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद नामक अपने दर्शन में उन्होंने दिखाया कि यह परिवर्तन कोई कपोल कल्पना नहीं है, इसका आधार विज्ञान है। दुनिया के सर्वहारा वर्ग को भी मार्क्सवादी दर्शन में पूँजीवादी शोषण के खिलाफ संघर्ष का एक ताकतवर हथियार मिला था। धीरे-धीरे कार्ल मार्क्स की सीख सारी दुनिया में फैल गयी और इसने मजदूर वर्ग के अंदर चेतना पैदा की। सन् 1864 में कार्ल मार्क्स के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन 'इंटरनेशनल वर्किंग मेन्स एसोसिएशन' का जन्म हुआ।

क्रांति के पहले का रूस

इस बीच निरंकुश जारशाही के जमाने में रूस में पूँजीवाद का धीरे-धीरे विकास हो रहा था। मार्क्स की सीख धीरे-धीरे वहाँ भी पहुँची। लेनिन के अनुसार ''मार्क्स-एंगेल्स को रूसी भाषा की बखूबी जानकारी थी, वे रूसी किताबें भी पढ़ते थे। रूस के बारे में उन्हें काफी दिलचस्पी थी और वहाँ के क्रांतिकारियों के साथ उनका रिश्ता भी था।'' (वॉल्यूम 2 पेज-19) मार्क्सवादियों के आगमन के पहले तक रूस के जार-विरोधी आंदोलन में

(शेष पृष्ठ 4 पर)

प्रशांत भूषण पर किये गये जघन्य हमले की एसयूसीआई(कम्युनिस्ट) द्वारा कड़ी भर्त्सना

एसयूसीआई(कम्युनिस्ट) के महासचिव कॉमरेड प्रभाष घोष ने 13 अक्तूबर, 2011 को जारी एक बयान में कहा : '' देश के एक अग्रणी सामाजिक कार्यकर्ता और भारत के सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील श्री प्रशांत भूषण पर किये गये नृशंस हमले की सोशलिस्ट यूनिटी सेन्टर ऑफ इण्डिया (कम्युनिस्ट) कड़ी भर्त्सना करती है और इस करतूत के पीछे जो ताकतें हैं उन्हें उजागर करने के लिए इस वारदात की गहन जांच कराने की मांग करती है। पार्टी यह भी मांग करती है कि दोषियों को उदाहरणमूलक सजा दी जाए।

कॉमरेड प्रभाष घोष ने आगे कहा कि यह डराने-धमकाने और विरोधी की आवाज को दबाने के मकसद से पैदा किया गया एक फासीवादी रुझान है जो हमारे समाज में न केवल बढ़ता जा रहा है बल्कि इसका बोलबाला होता जा रहा है। यह रुझान विभिन्न धर्मों को प्रश्रय व प्रोत्साहन दिये जाने और इस प्रकार समाज की धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक अवधारणा की प्राणसत्ता को ही कमजोर करने की लम्बे अर्से से जारी प्रैक्टिस का नतीजा है। असली धर्मनिरपेक्ष राज्य धर्म के सवालों पर तटस्थता का सख्ती से पालन करता है और धर्म को नागरिकों का व्यक्तिगत मामला मानता है। देश में एक पर एक आई सभी सरकारों द्वारा इन सिद्धांतों के किये गये उल्लंघन ने घोर धर्मोन्मादी रुझान पैदा कर दिये हैं जो हमारे समाज के मूलाधार को ही अन्दर से चट करते जा रहे हैं और सामाजिक प्रगति को बाधित करते जा रहे हैं। धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक मूल्यों को बुलन्द करते हुए एक सचेत संघर्ष के जरिए ही इस बुराई को मिटाया जा सकता है।''

एआईडीएसओ का छठा दिल्ली राज्य छात्र सम्मेलन

28 सितम्बर को शहीद भगतसिंह जयंती पर ऑल इण्डिया डेमोक्रेटिक स्टूडेन्टस ऑर्गेनाइजेशन (एआईडीएसओ) दिल्ली का छठा राज्य स्तरीय छात्र सम्मेलन दिल्ली विश्व विद्यालय की आर्ट फैकल्टी के टैगोर हाल में सम्पन्न हुआ। पहले नॉर्थ कैम्पस से झण्डे-बैनरों से सुसज्जित व अनुशासित जुलूस सम्मेलन स्थल टैगोर हाल तक निकाला गया। इसमें विभिन्न स्कूल-कॉलेजों के छात्र-छात्राओं ने उत्साह के साथ भाग लिया। सम्मेलन स्थल पर लगाई गई शहीद भगत सिंह के चित्र व उद्धरण प्रदर्शनी का उद्घाटन प्रो. नरेन्द्र शर्मा ने किया। शहीद वेदी पर पुष्पांजलि अर्पित कर आजादी आन्दोलन की गैर-समझौतावादी धारा के क्रांतिकारियों व जनवादी छात्र आन्दोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इनमें सम्मेलन के मुख्य अतिथि दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस राजेन्द्र सच्चर, प्रो. नरेन्द्र शर्मा, एसयूसीआई(कम्युनिस्ट) के दिल्ली राज्य सचिव कॉमरेड प्रताप सामल, एआईडीएसओ के महासचिव कॉ. सौरभ मुखर्जी, एआईडीएसओ के अखिल भारतीय उपाध्यक्ष कॉ. जुबैर रब्बानी व सुब्रतो गौरी, दिल्ली राज्याध्यक्ष कॉ. भास्करानंद, संगठन की उ.प्र. राज्याध्यक्ष कॉ. झरना मालवीय आदि प्रमुख थे। सम्मेलन की अध्यक्षता कॉमरेडस भास्करानंद, विनय कुमार व रितम्भरा को लेकर गठित अध्यक्ष मण्डल द्वारा की गई।

सम्मेलन के खुले अधिवेशन में उद्घाटन भाषण जस्टिस राजेन्द्र सच्चर ने दिया। उन्होंने शिक्षा की अनदेखी करने के सरकारी रवैये की कड़ी आलोचना की। इस अधिवेशन को कॉ. प्रताप सामल और प्रो. नरेन्द्र शर्मा ने भी सम्बोधित किया। उन्होंने शिक्षा के निजीकरण -व्यापारीकरण की पृष्ठभूमि पर विस्तार से चर्चा की। कॉमरेड सौरभ मुखर्जी ने अपने सम्बोधन में पूंजीपति वर्ग के हित साधने के लिए सरकार द्वारा लागू की जा रही विभिन्न नीतियों का खुलासा किया। उन्होंने दिखाया कि शिक्षा का यह व्यापारीकरण किस तरह मानवीय मूल्यों पर बुरा असर डाल रहा है और शिक्षा के असली मकसद - मानव निर्माण, चरित्र निर्माण - को ही विकृत कर रहा है। कॉमरेड सौरभ मुखर्जी द्वारा दिये गये समापन भाषण के साथ सम्मेलन के इस सत्र का समापन हुआ।

सम्मेलन के प्रतिनिधि अधिवेशन को सम्बोधित करते हुए एसयूसीआई(कम्युनिस्ट) के पोलिट ब्यूरो सदस्य कॉमरेड कृष्ण चक्रवर्ती ने शिक्षा के निजीकरण-व्यापारीकरण को लागू करने वाली नीतियों की पूरी पृष्ठभूमि, इसके कारण और निदान का खुलासा करते हुए कहा कि यह पूंजीवादी व्यवस्था गहरे संकट में फंस चुकी है। इस संकट से उबरने और अधिकतम मुनाफा कमाने के लिए निजीकरण-व्यापारीकरण की नीतियां लागू की जा रही हैं। इन छात्र-विरोधी और शिक्षा-विरोधी नीतियों के खिलाफ छात्र आन्दोलन न छिड़ जाए, इस सम्भवना को कम से कम करने के लिए छात्रों के जनवादी अधिकारों का हनन किया जा रहा है। प्रतिनिधि अधिवेशन में लगभग 100 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अधिवेशन में पेश किये गये प्रस्ताव पर खुली चर्चा-बहस हुई। शिक्षा पर फिलहाल लगातार हो रहे हमलों पर एआईडीएसओ का मत इस प्रस्ताव में समाहित है।इसमें सरकार की साजिश के खिलाफ जोरदार छात्र आन्दोलन गठित करने की अपील की गई ताकि शिक्षा को बचाया जा सके। दीपक रंजन द्वारा इस प्रस्ताव का समर्थन किया गया और सदन द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया।

(शेष पृष्ठ 7 पर)

व्यक्तिवाद का शिकार होने से सर्वहारा क्रान्तिकारी चरित्र हासिल करना सम्भव नहीं

कॉमरेड शिवदास घोष स्मृति दिवस पर घाटशिला की सभा में कॉमरेड रणजीत धर

सर्वहारा के महान नेता कॉमरेड शिवदास घोष की 35वीं मृत्यु वार्षिकी 5 अगस्त को झारखण्ड राज्य के सिंहभूम जिला के घाटशिला स्थित मार्क्सवाद-लेनिनवाद-कॉमरेड शिवदास घोष चिन्तनधारा अध्ययन केन्द्र में गहरी श्रद्धा के साथ मनाई गई थी।

उस दिन सुबह अध्ययन केन्द्र के प्रांगण में कॉमरेड शिवदास घोष की आदमकद प्रतिमा पर फूलों के हार चढ़ा कर एस.यू.सी.आई.(सी) के पोलिट ब्यूरो सदस्य कॉमरेड रणजीत धर और पार्टी के झारखण्ड राज्य सांगठनिक कमेटी सचिव कॉमरेड हेम चक्रवर्ती (जिनका अब निधन हो चुका है) व अध्ययन केन्द्र की ओर से कॉमरेड मलय बोस ने श्रद्धांजली दी। पार्टी के विभिन्न जन-संगठनों के नेताओं ने भी पुष्पांजली अर्पित की।

दोपहर को अध्ययन केन्द्र के हाल में स्मृति सभा आयोजित हुई। राज्य के कोने-कोने से आए कार्यकर्ताओं समर्थकों व हमदर्दों ने सभा में शिरकत की। पार्टी की राज्य संगीत मण्डली की ओर से कॉमरेड शिवदास घोष पर रचित गान पेश करने के साथ सभा की शुरूआत हुई। सभा की अध्यक्षता कॉमरेड हेम चक्रवर्ती ने की। मुख्य वक्ता कॉमरेड रणजीत धर थे।

कॉमरेड रणजीत धर ने कहा कि आज के इस खास दिन हम सब यह विचार करके देखें कि कॉमरेड शिवदास घोष की शिक्षाओं को हमने अपने जीवन में कहाँ तक तक लागू किया है। उनके द्वारा दिखाए गए रास्ते पर हम कितना आगे बढ़ पाए हैं और हम कॉमरेड शिवदास घोष की शिक्षाओं के आधार पर रोजमर्रे के संघर्ष कितने करते जा रहे हैं। फिर इस खास दिन हम सिर्फ उन्हें याद ही नहीं करते हैं, बल्कि उनके जीवन-संघर्ष के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा भी करते हैं।

उन्होंने कहा कि सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में ही पूँजीवाद आज घोर संकट में फंसा हुआ है। अमीर साम्राज्यवादी देशों से लेकर विकासशील व पिछड़े सभी पूँजीवादी देशों में जनता पर जबरदस्त आर्थिक मन्दी, मुद्रास्फीति, बेइंतहा महंगाई, बेरोजगारी का असहनीय बोझ लादा जा रहा है। आए दिन यहाँ वहाँ जन विक्षोभ फूट पड़ रहा है। लेकिन इन विक्षोभात्मक आन्दोलनों को सही रास्ते पर नेतृत्व देकर पूँजीवाद उखाड़ फेंककर शोषण से मुक्ति के आकांक्षित लक्ष्य पर पहुँचने की घटना भी उसी तरह देखने में नहीं आ रही है।

जबकि दूसरे विश्वयुद्ध के तुरन्त बाद ही दुनिया में हालात बिल्कुल अलग थे। सोवियत यूनियन के हाथों फासिस्ट ताकतों की हार हुई थी। जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था और सारी पूँजीवादी दुनिया में सामाजिक परिवर्तन के लक्ष्य से आन्दोलन की जबरदस्त लहर उठ खड़ी हुई थी। गरीब मजदूर-किसानों मध्यमवर्गीय लोगों से लेकर समाज के बुद्धिजीवी तबके, कलाकार, साहित्यकार, शिक्षक, अध्यापक, डाक्टर, इन्जीनियर झुण्ड के झुण्ड में समाजवाद की ओर झुकने लगे थे। आलम यह था कि लगता था मानो हम विश्व क्रान्ति की दहलीज पर आ पहुँचे हैं। लेकिन अचानक पीछे हटने लगे। ऐसा क्यों हुआ? पुराने तमाम कॉमरेडों को पता है और कॉमरेड शिवदास घोष के उस समय के लेख 'साम्यवादी खेमे की आत्म आलोचना' पुस्तक में भी पाएंगे कि विश्व साम्यवादी आन्दोलन की उस जबरदस्त लहर के समय ही कॉमरेड शिवदास घोष ने अन्तर्राष्ट्रीय नेतृत्व को मानते हुए ही साम्यवादी आन्दोलन में द्वन्द्वात्मक रिश्ते की बजाए यांत्रिक रिश्ते का प्रभाव दिखाई दे रहा है–यह चेतावनी देते हुए कहा था कि तुरन्त इस कमी-खामी से साम्यवादी आन्दोलन को मुक्त नहीं किया गया तो भविष्य में गड़बड़ हो सकती है। दरअसल हुआ भी ऐसा ही। हमारे देश में सीपीआई-सीपीआई(एम) को ही देख लीजिए। पहले जब वे एक पार्टी सीपीआई में थे, उन्होनें पूरी तरह यांत्रिक ढंग से यानी अन्धे की तरह रूस की पार्टी का अनुकरण किया। बाद में दो पार्टियों में विभाजित हो जाने के बाद सीपीआई ने रूस की पार्टी का और सीपीएम ने चीन की पार्टी का अंधानुकरण किया। इसके बाद सीपीएम से जब नक्सलपन्थी बाहर निकल आए और चीनपंथी हो गये तो सीपीएम ने किसी की ओर न जाकर मध्यम मार्गी बनकर भी दरअसल सोवियत की ओर दोबारा झुकना शुरू कर दिया। इस यांत्रिकता के अंजाम के तौर पर ही हमने देखा कि वैचारिक मतभेदों को केन्द्र करके अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवादी खेमा सोवियत रूस और चीन, दो भागों में बंट गया। तब केवल हमारे देश में ही नहीं बल्कि दुनिया के लगभग तमाम देशों में ही कम्युनिस्ट पार्टियाँ अंधे की तरह यांत्रिक तौर पर सोवियत रूस और चीन इन दो खेमों में बंट गईं।

कॉमरेड रणजीत धर ने कहा कि अन्तर्राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ विभिन्न देशों की कम्युनिस्ट पार्टियों का और हर देश की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ दूसरे देशों की कम्युनिस्ट पार्टियों का आपसी रिश्ता जहाँ द्वन्द्वात्मक रिश्ते के आधार पर संचालित करने की जरूरत थी, वहीं एक देश की मार्क्सवादी-कम्युनिस्ट पार्टी के अन्दर भी नेता-कार्यकताओं के रिश्ते, नेता-नेता के बीच रिश्ते, कार्यकर्ता-कार्यकर्ता के बीच रिश्ते की रीति भी द्वन्द्वात्मक होनी चाहिए थी। इस द्वान्द्वात्मक रिश्ते के आधार पर पार्टी को तभी संचालित किया जा सकता है जब पार्टी का अन्दरूनी माहौल खुला हो, जिसमें मन खोलकर सभी अपनी बात रख सकें, तर्क-वितर्क कर सकें और उसके जरिए सामूहिक फैसले पर पहुँच सकें। इस तर्क-वितर्क का उद्देश्य खुद का मत दूसरे पर थोप देना नहीं है, बल्कि दूसरे की बातों के आधार पर खुद के मत को विचारना है। क्योंकि कम्युनिस्ट सत्य के साधक होते हैं। सत्य को जानकर सच्चाई के रास्ते पर चलना ही कम्युनिस्टों की जीवन साधना है।

उन्होंने आगे कहा कि नकल करके किसी देश में क्रान्ति नहीं होती है। सत्य होता है विशेष सत्य। हर देश के आर्थिक और सामाजिक विकास की आम प्रक्रिया के अन्दर भी अपनी अपनी कुछ विशेषताएं रहती हैं। उन विशेषताओं को मद्देनज़र रखकर उस देश की क्रान्ति की लाइन तय करनी होती है। यह एकमात्र उस देश की सही मार्क्सवादी पार्टी ही कर सकती है। इसलिए क्रान्ति के लिए चाहिए सही क्रान्तिकारी पार्टी। सही क्रान्तिकारी पार्टी के बिना किसी भी देश में क्रान्ति सफल नहीं हो सकती। आज दुनिया में सर्वत्र देख लीजिए। सिर्फ रूस, अफ्रीका, लैटिन अमेरिकी देशों में ही नहीं बल्कि पश्चिम के विकसित साम्राज्यवादी देशों में भी लोगों का आए दिन विक्षोभ फूट पड़ रहा है। लेकिन जब तक इन सब आन्दोलनों में क्रान्तिकारी नेतृत्व कायम नहीं होगा, तब तक कोई भी आन्दोलन आकांक्षित लक्ष्य तक नहीं पहुँच पाएगा।

उन्होंने कहा कि पूँजीवाद-विरोधी समाजवादी क्रान्ति एक खास तरह की क्रान्ति होती है। इस क्रान्ति की संस्कृति के अनुसार कॉमरेडों को खुद को बदल डालना होगा। इसके बिना काम नहीं चलेगा। समाजवादी क्रान्ति है व्यक्तिगत मालिकाने की जगह सामाजिक मालिकाना कायम करने का संघर्ष। इस संघर्ष में हमारे सामने सबसे बड़ी बाधा व्यक्तिवाद है। मरणासन्न पूँजीवाद के युग में व्यक्तिवाद घोर प्रतिक्रियावादी हो चुका है। यह व्यक्तिवाद समाज को नहीं जानता। यहाँ तक कि अपनी पत्नी-पुत्र-पुत्री तक को नहीं जानता। यह सिर्फ खुद को जानता है। यह व्यक्तिवाद जब तक हमारे अन्दर रहेगा तब तक हमारे

लिए सर्वहारा क्रान्तिकारी चरित्र हासिल करना सम्भव नहीं होगा। हमारे छोटे-छोटे मोह, पारिवारिक कर्त्तव्यबोध, जरा से ऐशो-आराम क्रान्ति से हमें दूर धकेल देते हैं, जिसने एक दिन सब कुछ क्रान्ति की जरूरत के लिए छोड़ दिया था, वह भी तुच्छ व्यक्तिगत स्वार्थों के सामने खुद को सही सलामत नहीं रख पाता है, इसके अलावा जो यह सोचता है कि सब काम सम्भालने के बाद क्रान्ति का काम करूँगा, उसके लिए वह दिन कभी नहीं आएगा, पूँजीवाद वह दिन आने ही नहीं देगा। मैं यह अनुरोध करता हूँ कि आप कॉमरेड शिवदास घोष के चिंतन की रोशनी में खुद को बदल डालें। खुले मन से आलोचना को स्वीकार करें। तर्क करें लेकिन खुद को प्रतिष्ठित करने या दिखावा करने के लिए न करें। तर्क करें जानने के लिए। सर्वहारा संस्कृति अपनाने के संघर्ष में खुद को लगा दें। कॉमरेड शिवदास घोष कहा करते थे कि प्रत्येक दर्शन की प्राण सत्ता ही होती है उसकी संस्कृति।

आज हमारे देश में क्रान्ति की जमीन चारों ओर तैयार है। कॉमरेड शिवदास घोष के हाथों तैयार सर्वहारा की सही क्रान्तिकारी पार्टी एसयूसीआई(कम्युनिस्ट) भी है। सिर्फ जरूरत है उपयुक्त शक्ति की। वह शक्ति हमें जल्दी से जल्दी हासिल करनी होगी। देश में जो सब राजनैतिक पार्टियाँ हैं यानी कांग्रेस, बीजेपी, लोक जन शक्ति, समाजवादी पार्टी, तेलगू देशम, सीपीएम, आरजेडी, जेएमएम, तृणमूल कांग्रेस–ये सभी पूँजीपति वर्ग के साथ खड़ी हैं। राँची, टाटानगर सभी जगह जहाँ बस्तियाँ उजाड़ी जा रही हैं, वहीं हम यह नजारा साफ देख पा रहे हैं। जबकि दूसरी ओर हमारी पार्टी आम लागों के साथ खड़ी रहकर आन्दोलन चला रही है। इन आन्दोलनों को केन्द्र करके ही पार्टी का संगठन बढ़ रहा है। लेकिन क्रान्ति के लिए आवश्यक उपयुक्त सांगठनिक शक्ति आज भी हम हासिल नहीं कर पाएं हैं। साथ ही साथ उन्नत सर्वहारा संस्कृति अपनाने का संघर्ष भी अगर हम लगातार चला पाए तभी हम वांछित लक्ष्य पर पहुँच पाएंगे। इस काम में खासकर छात्र-नौजवानों को आगे आना होगा। क्योंकि हर देश में ही छात्र-नौजवानों ने क्रान्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अन्तर्राष्ट्रीय गान के साथ सभा का समापन हुआ।

ज्वलंत समस्याओं को लेकर उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन

एस.यू.सी.आई. (कम्युनिस्ट) पूर्वी सिंहभूम जिला कमिटी के आह्वान पर जिला के विभिन्न ज्वलंत समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर जमशेदपुर में उपायुक्त कार्यालय के समक्ष जोरदार प्रदर्शन किया गया। जमशेदपुर और सुदूर ग्रामीण इलाकों से भी लोग प्रदर्शन में शामिल हुए थे। नारों, बैनरों, प्लेकार्डों से सुसज्जित एक भव्य जुलूस साकची आमबगान मैदान से निकलकर उपायुक्त कार्यालय पहुंचा। जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे पार्टी के पूर्वी सिंहभूम जिला कमिटी के सदस्य कॉमरेड विमल दास, सीताराम टुडू, रूद्र दास, सरला महतो, सुमित राय, सोनोका महतो, धीरेन भगत, अमित राय, सुनील महतो। आसमान छूती महंगाई पर रोक लगाने, मजदूरों का न्यूनतम वेतन बढ़ाने, एपीएल बीपीएल सभी को राशन कार्ड व राशन मुहैया कराने, महिला उत्पीड़न की घटनाओं में लगातार हो रही वृद्धि पर रोक लगाने के लिए ठोस कार्यवाई करने, बीपीएल सर्वे नये सिरे से करने, मनरेगा, इंदिरा आवास आदि योजनाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार पर रोक लगाने, स्कूल-कॉलेजों में व्याप्त शिक्षकों की जबरदस्त कमी को दूर करने, शिक्षकों को गैर-शैक्षणिक कामों से दूर रखने की मांग की गई। एक 6 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त महोदया के नाम 13 सूत्री मांगों से संबंधित एक ज्ञापन सौंपा।

मारुति-सुजूकी के मजदूरों का एआईयूटीयूसी द्वारा समर्थन

रोहतक (हरियाणा): 15 अक्तूबर को केन्द्रीय श्रमिक संगठन-ऑल इण्डिया यूटीयूसी ने मारुति-सुजूकी कम्पनी द्वारा मानेसर (गुड़गांव) में श्रमिकों पर किये जा रहे घेर अन्याय, जोर जबरदस्ती व ज्यादतियों का कड़ा विरोध किया है और हरियाणा सरकार की कम्पनी से मिलीभगत की निन्दा की है। एआईयूटीयूसी के प्रदेश अध्यक्ष कॉमरेड सत्यवान ने कहा कि सुजूकी कम्पनी ने श्रमिकों के साथ हुए समझौते को एकतरफा तोड़कर उन्हें काम पर लेने से इन्कार कर दिया और अपनी मनमानी चालू रख कर श्रमिकों को दुबारा आन्दोलन के लिए मजबूर कर दिया।

उन्होंने कहा कि सुजूकी कम्पनी मजदूरों पर मनमानी शर्तें थोप रही है। उनके मौलिक व संवैधानिक अधिकारों का हनन कर रही है। पुलिस, प्रशासन व हरियाणा सरकार की इसमें मिलीभगत है। श्रमिकों को लगातार डराया, धमकाया व दबाया जा रहा है। फैक्ट्री में पहलवान टाइप गुण्डे-बाउन्सरों को तैनात कर रखा है जो श्रमिकों की एकता व शान्तिपूर्ण विरोध को विफल करने व कुचलने पर 24 घण्टे उतारू हैं। ठेकेदार भी गुण्डागर्दी कर रहे हैं। विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के नाम पर प्रदेश सरकार, प्रशासन व श्रम विभाग मारुति कम्पनी की इन सब मनमानी व अपराधपूर्ण कार्यवाहियों के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा रहे।

कॉ. सत्यवान ने कहा कि श्रमिकों को अपनी पसन्द की यूनियन बनाने, अपनी मांगे मनवाने, अन्याय का विरोध करने, आन्दोलन करने के मौलिक अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। प्रदेश के आम जन को उनका समर्थन करना चाहिए। श्रमिक प्रदेश में जनतन्त्र की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस संघर्ष में ऑल इण्डिया यूटीयूसी उनके साथ है। आगामी 17 अक्टूबर को जिला मुख्यालयों पर धरने, प्रदर्शन करके एआईयूटीयूसी संघर्षरत मारुति श्रमिकों के समर्थन में अपनी आवाज उठायेगा।

मारुति-सुजूकी प्रबंधन की मनमानी के खिलाफ ट्रेड यूनियनों ने किया संयुक्त प्रदर्शन

भिवानी (हरियाणा): गुड़गांव-मानेसर मारुति-सुजूकी के मजदूरों के समर्थन में 17 अक्टूबर को ट्रेड यूनियनों ने शहर में प्रदर्शन किया। डी.सी. भिवानी के मार्फत हरियाणा राज्यपाल को ज्ञापन प्रेषित किया। ज्ञापन में मांग की गई कि मर्जी की यूनियन बनाने का मजदूरों का अपना अधिकार है, इसे बहाल किया जाए तथा ट्रेड यूनियन अधिकारों का सम्मान किया जाए। सभी श्रम कानून लागू हों तथा हरियाणा में श्रमिकों के साथ मारुति मैनेजमैंट जो दमन पर उतारू है, उसे रोका जाए। प्रदर्शनकारियों को सीटू के नेता अनिल कुमार, एआईयूटीयूसी के कॉमरेड जिले सिंह, भवन निर्माण कारीगर मजदूर यूनियन के कॉ. धर्मवीर, सर्वकर्मचारी संघ के नेता रतन जिन्दल व ओमप्रकाश सैनी ने संबोधित किया। वक्ताओं ने अपने संबोधन में हरियाणा सरकार व श्रम विभाग के मजदूर विरोधी रुख की कड़े शब्दों में निन्दा करते हुए कहा कि सरकार व प्रशासन खुलकर उनके पक्ष में खड़ा है, जो मजदूरों की खाल उतारते हैं, उनका बुरी तरह शोषण करते हैं तथा उन पर तानाशाही ढंग से दमन करते हैं। सरकार के इस निन्दनीय व मजदूर-विरोधी कदम की भर्त्सना करते हुए सभी नेताओं ने 8 नवम्बर को श्रमिक संघों की राष्ट्रव्यापी कार्यवाही में बढ़-चढ़कर भाग लेने का संकल्प लिया और कहा कि उदारीकरण, निजीकरण व वैश्वीकरण के सत्यानाशी एजैण्डा के खिलाफ मजदूर मेहनतकश आर-पार का संघर्ष लड़ेंगे। महंगाई, भ्रष्टाचार व शोषण की ताकतों को उखाड़ फेंकेंगे।

रेवाड़ी: ऑल इण्डिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सैन्टर (ऑल इण्डिया यूटीयूसी) रेवाड़ी के सचिव कॉ. बलराम ने जिला उपायुक्त कार्यालय के समक्ष प्रदर्शनकारी मजदूरों को सम्बोधित करते हुए कहा कि मारुति-सुजूकी के मानेसर प्लांट में श्रमिकों के साथ लम्बे समय से जो कुछ हो रहा है वह अमानवीय है तथा जनवादी अधिकारों के विरुद्ध है।

आसाम में कालेज चुनाव में एआईडीएसओ की जीत

गुवाहाटी में कामाख्या राम बरूआ गर्ल्स कॉलेज में महासचिव के पद पर त्रिकोणीय मुकाबले में ऑल इण्डिया डीएसओ की उम्मीदवार विजयी हुई। इससे छात्राओं में उत्साह का संचार हुआ जिन्होंने अपनी जायज मांगों को पूरी करवाने के लिए उच्च नीति-नैतिकता व संस्कृति के आधार पर जोरदार छात्र आन्दोलन गठित करने के बारे में ऑल इण्डिया डीएसओ पर जबरदस्त विश्वास जताया है।

महंगाई के खिलाफ जमशेदपुर में विरोध प्रदर्शन

बढ़ती महंगाई, पानी की किल्लत, विस्थापन, शिक्षा के निजीकरण व्यापारीकरण, महिलाओं पर अत्याचारों के खिलाफ एसयूसीआई(कम्युनिस्ट) पूर्वी सिंहभूम जिला कमेटी की ओर से 12 सितम्बर को जमशेदपुर में विरोध प्रदर्शन किया गया। कॉमरेड्स विमल दास, सीताराम टुडु, सुमित राय, धीरेन भगत, सोनोका महतो, सरला महतो, रूद्र दास, सुनील महतो ने इसकी अगुआई की। डी सी द्वारा ज्यादातर मांगें मान ली गईं।

किसानों ने किया प्रदर्शन

रेवाड़ी (हरियाणा) : 15 अक्तूबर को ऑल इण्डिया कृषक खेत मजदूर संगठन ने डीएपी खाद की मूल्य वृद्धि कम करने, बाजरे की खरीद शुरू करने व पर्याप्त बिजली देने की मांग को लेकर धरना-प्रदर्शन किया। संगठन के कार्यकर्ता राव तुलाराम पार्क में एकत्रित हुए और प्रदर्शन करते हुए जिला सचिवालय पहुंचकर धरना दिया। इसका नेतृत्व जिला सचिव कॉमरेड रामकुमार ने किया। ज्ञापन लेने के लिए जिला उपायुक्त व उनका कोई प्रतिनिधि नहीं आने के कारण ज्ञापन की प्रति सचिवालय के मुख्य द्वार पर चस्पा कर दी गई। ज्ञापन में कहा गया कि किसान-खेत मजदूरों की समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं। आवश्यक वस्तुओं के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। डीएपी खाद के दामों में हुई लगभग दोगुनी वृद्धि ने किसानों की कमर तोड़ दी है। किसानों को बाजरा सस्ते दामों पर बेचना पड़ रहा है। बिजली कटौती ने किसानों को बेहाल कर दिया है। खेती-बाड़ी घाटे का सौदा बन गई है। किसानों ने डीएपी खाद के बढ़ाए दाम वापस लेने, बाजरे की सरकारी खरीद शुरू करने, जिन किसानों ने बाजरा बेच दिया है उनकी भरपाई करने तथा किसानों को पर्याप्त बिजली देने की मांग की गई। प्रदर्शन को संगठन के प्रांतीय सचिव कॉमरेड विजय कुमार, जिला प्रधान जयनारायण व बलराम, एसयूसीआई(कम्युनिस्ट) के जिला सचिव कॉ. राजेन्द्र सिंह एडवोकेट ने संबोधित किया।

सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन

शिवपुरी (म.प्र.): 16 अक्तूबर को स्थानीय कर्मचारी भवन में शहीद भगतसिंह विचार मंच और डीवाईओ की शिवपुरी इकाई द्वारा शहीद भगतसिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित करके उनकी याद में स्मृति सभा व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम में उद्घाटन भाषण बादशाह कुशवाह ने रखा। शहीद भगतसिंह के जीवन संघर्ष का परिचय सौरभ पिंहल ने रखा। इसके पश्चात् राखी जैमिनी, ईशु राजपूत, भूरेलाल लाखेरा, मुमीन अहमद मुमीन, राहुल जैन, राहुल लक्ष्यकार कृष्ण कुमार द्वारा देश-भक्ति जनवादी गीत, गजल की प्रस्तुति की गई।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि शहर के वरिष्ठ नागरिक और शिक्षा जगत के समाजसेवी श्री मधुसुदन चौबे रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता भगतसिंह यादगार मंच के (म.प्र.) के संयोजक और डीवाईओ के राज्य प्रभारी लोकेश शर्मा ने की। उन्होंने कहा कि आज समाज के उदासीन माहौल और दमघोटू हालात में शहीद भगतसिंह के विचार अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिये प्रेरणा देते हैं। साथ ही उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों से अपील की कि भगतसिंह के सपनों का भारत बनाने के लिए भगतसिंह मंच द्वारा संचालित वैकल्पिक, राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आन्दोलन में सक्रिय भूमिका देने की अपील की।

कार्यक्रम में आभार नरेन्द्र धाकड़ ने व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन संगठन के जिला प्रभारी सुरेन्द्र कुमार ने किया ''मेरा रंग दे बसंती चोला'' गीत के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शहर के वरिष्ठ नागरिकों सहित महिलाएं, पुरुष, छात्र-नौजवान आदि शामिल रहे।

सस्ती खाद, बिजली देने व बाजरे की सरकारी खरीद शुरू करने की माँग पर

किसानों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा

तोशाम (हरियाणा): हरियाणा में बढ़ती महंगाई, किसानों पर कर्ज की मार, डीजल व डीएपी खाद जैसी महत्वपूर्ण उपभोग की चीजों की कीमतों में बढ़ोतरी, डीएपी खाद पर किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी में कटौती और बाजरे की सरकारी खरीद नहीं होने से किसानों की फसल मजबूरीवश व्यापारियों को कोड़ियों के भाव बेचने की समस्याओं को लेकर ऑल इण्डिया कृषक खेत मजदूर संगठन की स्थानीय इकाई ने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन उपमण्डल अधिकारी (नागरिक), तोशाम (जिला भिवानी) की मार्फत भेजा। किसान नेता कॉ. जिले सिंह की अगुआई में प्रतिनिधि मण्डल 6 अक्टूबर को एसडीएम से मिला और उक्त ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई कि डीएपी खाद पर सब्सिडी बहाल की जाए, बाजरे की खरीद सरकारी रेट पर शीघ्र शुरू की जाये, कृषि क्षेत्र के लिए बिजली कम से कम 12 घण्टे दी जाए और डीजल के रेट आधे किये जाएं।

शैक्षणिक समस्याओं को लेकर वी सी कार्यालय पर छात्र प्रदर्शन

रांची (झारखण्ड): 26 सितम्बर को ईश्वरचंद्र विद्यासागर जयंती एआईडीएसओ रांची जिला कमेटी द्वारा 'शिक्षा बचाओ - मानवता बचाओ दिवस' के तौर पर मनायी गई और शिक्षा पर हो रहे हमलों के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया गया। सरकार की शिक्षा-विरोधी नीतियों के खिलाफ नारे लगाते हुए रांची जिला के विभिन्न स्कूल-कॉलेजों के छात्र-छात्राओं का जुलूस जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से शहीद चौक के पास स्थित रांची विश्वविद्यालय पहुंचा।

संगठन का एक प्रतिनिधिमण्डल रांची विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर ए ए खान से मिला और उन्हें 12 सूत्री मांगों का एक ज्ञापन सौंपा। इसमें मांग की गई कि बेतहासा फीस वृद्धि, सिलेबस अधूरा छोड़ देने, समेस्टर प्रणाली, सीट कटौती, बीपीएल परिवारों के छात्रों से भारी फीस वसूली और छात्राओं को पीजी स्तर तक नि:शुल्क शिक्षा का प्रबन्ध न किये जाने पर रोष जताया गया। प्रतिनिधिमण्डल में एआईडीएसओ के राज्याध्यक्ष कॉ. मिंटू पासवान, संगठन की रांची जिला सचिव कॉ. शिखा कुमारी, जिला कार्यालय सचिव कॉ. सचिन कुमार और विभिन्न कॉलेजों के प्रतिनिधि, योगदा कॉलेज से संदीप कुमार व रमेश कुमार, जे एन कॉलेज से दुर्गेश कुमार, सिल्ली कॉलेज से निर्मला कुमारी शामिल थे।

महान नवम्बर क्रान्ति.....

(पृष्ठ 1 का शेष)

मुख्यत: नरोदनिकवाद का ही प्रभाव व्याप्त था। नरोदनिकवादी जारशाही का खात्मा तो चाहते थे लेकिन उनका मानना था कि यह काम दहशत पैदा कर व्यक्तियों की हत्या से ही संभव है। नरोदनिकवादियों का मानना था कि जारशाही के खात्मे के लिए कुछ जांबाज लोगों की सक्रिय वीरतापूर्ण भूमिका ही काफी है। इसमें आम जनता की कोई खास भूमिका नहीं है। महान स्तालिन के मुताबिक नरोदनिक सिद्धांत का आधार था –Active heroes and passive mobs यानी हीरो चुस्त और लोगों की भीड़ सुस्त। क्रांति में मजदूर वर्ग की नेतृत्वकारी भूमिका और उसके लिए उसकी अपनी क्रांतिकारी पार्टी की जरूरत को नरोदनिकवादी नकारते थे। इसलिए उनका सिद्धांत क्रांति का विरोधी था। रूस में मार्क्सवाद के सम्पर्क में सबसे पहले प्लेखानोव आये थे और वहाँ वे एक असाधारण प्रचारक के रूप में उभरे थे। हालांकि, वे अपने शुरूआती जीवन में नरोदनिकवाद में विश्वास करते थे। मार्क्स-एंगेल्स की प्रसिद्ध पुस्तक 'कम्युनिस्ट घोषणापत्र' का उनकी लिखी भूमिकाओं सहित उन्होंने रूसी भाषा में अनुवाद किया। मार्क्स-एंगेल्स की काफी रचनाओं का रूसी में अनुवाद हुआ। 1883 में रूस में प्लेखानोव ने ही सबसे पहले 'मजदूर-मुक्ति' ('Emancipation of Labour') नामक एक मार्क्सवादी ग्रुप की स्थापना की थी। इस ग्रुप ने नरोदनिकवाद के पैरोकारों के गलत सिद्धांतों के खिलाफ वैचारिक संघर्ष चलाकर मार्क्सवाद के पक्ष में पूरे देश में प्रचार किया। मार्क्सवादी दृष्टिकोण के आधार पर नरोदनिक सिद्धांत के खिलाफ वैचारिक संघर्ष चलाकर प्लेखानोव ने कुछ निबंध लिखे। इनमें खास तौर पर उल्लेखनीय है इतिहास के अद्वैतवादी दृष्टिकोण के विकास के बारे में' (On the development of the monistic view of history)। लेनिन के अनुसार इस निबंध ने 'रूस में मार्क्सवादियों की पूरी एक पीढ़ी को शिक्षित किया था'। यह सही है कि नरोदनिकवाद का खण्डन करके मार्क्सवाद आगे बढ़ा, लेकिन प्लेखानोव ने कुछ गंभीर गलतियाँ की थी। नरोदनिक दर्शन के खिलाफ कठोर संघर्ष छेड़ने के बावजूद उसका कुछ असर उनके चिन्तन में रह गया था। व्यक्ति-हत्या की राजनीति में उनका विश्वास था। मजदूर वर्ग के नेतृत्व में क्रांति में किसान समुदाय की सहयोगी भूमिका के बारे में उनका नजरिया साफ नहीं था। उनका सोचना था कि उदारवादी बुर्जुआ वर्ग मजदूरों के हितों की हिफाजत में मदद करता है। सर्वोपरि, तत्कालीन दूसरे मार्क्सवादी ग्रुपों की तरह उनके संगठन 'मजदूर-मुक्ति' ('Emancipation of Labour') का भी मजदूर आंदोलन के बारे में कोई वास्तविक अनुभव नहीं था।

प्लेखानोव की कमियों को दूर कर मार्क्सवाद के आधार पर मजदूर वर्ग के आंदोलन को निर्मित करने की जिम्मेवारी लेनिन पर आ पड़ी। क्रांतिकारी छात्र आंदोलन में शिरकत करने के 'जुर्म' में महज 18 साल की उम्र में ही लेनिन को काजान विश्वविद्यालय से निष्कासित कर पुलिस की हिरासत में ले लिया गया था। उस दौरान वे फेदोसेव द्वारा स्थापित एक मार्क्सवादी ग्रुप में शामिल हुए। बाद में समारा में जाकर उन्होंने स्वयं एक मार्क्सवादी ग्रुप की स्थापना की। 1893 में वे सेंट पीट्र्सबर्ग चले गये। इसके बाद 1895 में उन्होंने सारे मार्क्सवादी ग्रुपों को एकत्रित कर 'लीग ऑफ स्ट्रगल फोर द वर्किंग क्लास' (मजदूर वर्ग के मुक्ति-संघर्ष के लिए लीग) का गठन किया और मजदूरों को लेकर एक के बाद एक आंदोलन संगठित करना शुरू किया। लेनिन ही सबसे पहले उस देश में मजदूर आंदोलन में वैज्ञानिक समाजवाद की सीख लाये। रूस में उस समय भी नारदनिकवाद का प्रभाव था और लेनिन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'जनता के मित्र कौन हैं और सोशल डेमोक्रेटों से वे कैसे लड़ते हैं' ('What the friends of the people are and how they fight the social democrats') में इस सिद्धांत की गलतियों को उजागर किया। उस दौरान रूस में प्लेखानोव के ग्रुप

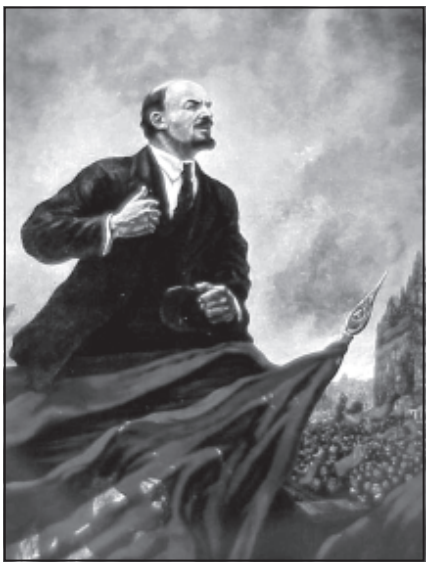

सहित तमाम मार्क्सवादी ग्रुपों को एकजुट कर मजदूरों की एक सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी निर्मित करने की कोशिश हो रही थी। (उस दौरान सोशल डेमोक्रेसी का अवसरवादी और समझौतापरस्त चरित्र साफ तौर पर उजागर नहीं हुआ था और इसलिए कम्युनिस्ट आंदोलन से सोशल डेमोक्रेटों को हटाया नहीं गया था) ठीक उसी समय 1897 में लेनिन की गिरफ्तारी हुई। उनको साइबेरिया में निर्वासित कर दिया गया। वहाँ रहकर भी लेनिन ने गुप्त रूप से कॉमरेडों के साथ सम्पर्क बनाये रखा और इस दौरान कुछ लेख भी लिखे। उस दौरान रूस के मजदूर आंदोलनों में अर्थवाद का रुझान काम कर रहा था। इसलिए मजदूर राजनैतिक-सैद्धांतिक चर्चा और पार्टी निर्माण की प्रक्रिया को छोड़कर महज आर्थिक मांगों को हासिल करने में ही व्यस्त थे। साइबेरिया में निर्वासन के दौरान लेनिन ने इस रुझान के खिलाफ काफी लेख लिखे।

ईस्क्रा का प्रकाशन

लेनिन की 'लीग ऑफ स्ट्रगल फोर द वर्किंग क्लास' सर्वहारा वर्ग की क्रांतिकारी पार्टी की बुनियाद थी। रूस के विभिन्न शहरों में लीग की शाखाएँ बन रही थीं। इसका लक्ष्य था रूस में सर्वहारा वर्ग की एक एकताबद्ध पार्टी की स्थापना करना।

1898 के मार्च में पुलिस की नजर बचाकर अच्छी तादाद में सोशल डेमोक्रेटिक संगठनों के प्रतिनिधि मिंस्क शहर में एकत्रित हुए। वहाँ 'रशियन सोशल डेमाक्रेटिक लेबर पार्टी'('आरएसडीएलपी') की स्थापना करने की घोषणा हुई। हालांकि, उस समय पार्टी की स्थापना नहीं की जा सकी। लेनिन निर्वासित थे। उनकी गैरमौजूदगी में संगठन के काम-काज में दिक्कतें आ रही थीं। बहुत जल्द ही पार्टी की केन्द्रीय कमिटी के सदस्य भी पुलिस की गिरफ्त में आ गये। दूसरे सोशल डेमोक्रेटिक संगठन अलग-अलग तरीके से अपने-अपने ढंग से काम करते रहे।

निर्वासन के दौरान लेनिन ने सारे सोशल डेमोक्रेटिक संगठनों को एकजुट कर पार्टी निर्माण की विस्तृत योजना तैयार की। उस दौरान उन्होंने एक ऐसे राजनैतिक पत्र के प्रकाशन की जरूरत महसूस की, जो पूरे रूस में फैले तमाम मार्क्सवादी ग्रुपों और संगठनों के बीच सम्पर्क कायम करे और पार्टी निर्माण का पथ प्रशस्त करे।

लेनिन ने निर्वासन से लौटने के बाद दिसम्बर 1900 में प्लेखानोव के साथ मिलकर 'ईस्क्रा' (चिंगारी) अखबार का पहला अंक प्रकाशित किया। उसके पहले पन्ने पर लिखा था 'चिंगारी ज्वाला भड़का देगी।' 'ईस्क्रा' देश के बाहर छपता था और प्रशासन की नजर बचाकर गुप्त रूप से रूस लाया जाता था। अखबार बाँटने के दौरान अगर कोई पकड़ा जाता, तो जार के सख्त निर्देश पर उसे जेल या निर्वासन की सजा होना तय था। लेकिन इतनी रुकावटों के बावजूद 'ईस्क्रा' का प्रचार रोका नहीं जा सका। पूरे रूस में यह अखबार फैल गया। विभिन्न शहरों में 'ईस्क्रा' के पाठकों और समर्थकों का संगठन खड़ा हो गया। ट्रान्स-कॉकेशिया में ऐसे ही एक संगठन के नेता थे स्तालिन। बाद में उनके सम्पादकत्व में जॉर्जिया में एक दूसरा राजनैतिक पत्र 'ब्राडजला'(संघर्ष) प्रकाशित हुआ।

आरएसडीएलपी का निर्माण

लेनिन के अखबार 'ईस्क्रा' की सफलता से पार्टी की दूसरी कांग्रेस को काफी मदद मिली। 1903 में लंदन में पार्टी की दूसरी कांग्रेस आयोजित हुई। इस कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य था पार्टी-कार्यक्रम निर्धारित करना और उसे लागू करना। आरएसडीएलपी की लंदन कांग्रेस में जिन कार्यक्रमों को अपनाया गया, वे एक सर्वहारा वर्ग की क्रांतिकारी पार्टी के जुझारू आंदोलन के कार्यक्रम थे। कहा गया कि पार्टी का मकसद है उत्पादन के साधनों से व्यक्तिगत मालिकाना खत्म करना, मानव द्वारा मानव का शोषण और वर्ग-विभाजित समाज का खात्मा करना। संक्षेप में, पूँजीवादी व्यवस्था का खात्मा करना और समाजवादी व्यवस्था की स्थापना करना। कार्यक्रम में कहा गया कि इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए समाजवादी क्रांति करनी होगी और सर्वहारा वर्ग का राज कायम करना होगा। इसके लिए सबसे पहले निरंकुश जारशाही का खात्मा करना जरूरी है ।

लेकिन महज कार्यक्रम निर्धारित कर लेने से ही काम नहीं चलता। पार्टी का सांगठनिक ढाँचा कैसा होगा और पार्टी अपनी जिम्मेवारियों का निर्वाह कैसे करेगी – इस संबंध में स्पष्ट रूपरेखा तय करना बेहद जरूरी हो गया। पार्टी के सांगठनिक नियमों के बारे में फैसला करना बहुत जरूरी हो गया। इन विषयों को लेकर पार्टी की दूसरी कांग्रेस में जबर्दस्त बहस शुरू हो गई। खास तौर पर बहस इस बात को लेकर शुरू हुई कि पार्टी के सदस्य कौन हो सकते हैं और कौन नहीं। दूसरी कांग्रेस में पार्टी में दो ग्रुप बन गये। लेनिन के नेतृत्व में जो बहुसंख्यक समूह था उसका नाम हुआ 'बोल्शेविक' और अल्पसंख्यक समूह का नाम हुआ 'मेंशेविक'। शुरू में प्लेखानोव लेनिन के साथ थे। लेकिन बाद में वे मेंशेविकों की ओर चले गये।

मेंशेविकों की मांग थी कि हर प्रोफेसर, हर छात्र, '' हर हड़ताली'' को, हर प्रदर्शनकारी को यह अधिकार दिया जाये कि वह खुद को पार्टी का सदस्य घोषित कर सके, विभिन्न विचारधाराओं वाले समूहों और व्यक्तियों को पार्टी की सदस्यता दी जाये। साथ ही बहुमत के प्रति अल्पमत के समर्पण की नीति को भी छोड़ दिया जाये। मेंन्शेविक केन्द्रीयता की नीति के विरोधी थे। वे स्वतंत्र व्यक्ति-चिंतन के समर्थक थे। वे पार्टी को लुंज-पुंज राष्ट्रीय पूछल्लावादी ('खवोटिस्ट') पार्टी बना देने के पक्षधर थे। वास्तव में रूस में तब बुर्जुआ जनवादी क्रांति दस्तक दे रही थी। इसलिए बुर्जुआ बुद्धिजीवी क्रांति के पक्ष में खड़े होकर अनेक समय पार्टी के काम में मदद करते थे। यही वजह है कि मेंशेविकों ने इन्हें पार्टी सदस्य बनाने की कोशिश की।

लेनिन का लक्ष्य था सर्वहारा वर्ग की एक क्रांतिकारी पार्टी का निर्माण करना। मेंशेविकों की अति क्रांतिकारिता और अराजक गतिविधियों के खिलाफ खड़े होकर लेनिन मजदूर वर्ग की एक क्रांतिकारी पार्टी का निर्माण करना चाहते थे, जिसका ढाँचा होगा मानव-देह जैसा (monolithic)। लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविकों ने दृढ़ता के साथ एलान किया:

1. मजदूर वर्ग और मजदूर वर्ग की पार्टी एक नहीं होती। मजदूर वर्ग की पार्टी उस वर्ग का वर्ग-सचेत और मार्क्सवादी विचारधारा से लैस अगुआ हिस्सा होती है।

2. पार्टी सिर्फ अगुआ हिस्सा ही नहीं है, मजदूर वर्ग का सबसे संगठित अगुआ दस्ता होती है। संगठन ही सर्वहारा वर्ग का एकमात्र हथियार होता है। इसलिए पार्टी सदस्यों को अनिवार्य रूप से किसी न किसी संगठन का सदस्य होना होगा।

3. सही तरीके से काम करने और जनता को अनुशासित तरीके से मार्ग दर्शन करनेके लिए मजदूर वर्ग को केन्द्रीयता की नीति के आधार पर पार्टी को

(शेष पृष्ठ 5 पर)

महान नवम्बर क्रान्ति.....

(पृष्ठ 4 का शेष)

संगठित करना होगा। यानी पार्टी में नेतृत्व को स्थापित करना होगा, निचले स्तर की कमेटियों को उच्चतर स्तर की कमेटियों के प्रति समर्पण भाव रखना होगा। पार्टी के हर स्तर के कार्यकर्ताओं और नेताओं को पार्टी का अनुशासन लाजिमी तौर पर मानना होगा।

4. संगठन का उच्चतम रूप है पार्टी। पार्टी ही दूसरे तमाम संगठनों को नेतृत्व प्रदान करेगी। इसलिए उन्नत विचारधारा से लैस, वर्ग-संघर्ष के कायदे-कानून और क्रांतिकारी आंदोलन के अनुभव से समृद्ध मजदूर वर्ग के सबसे अगुआ हिस्से को लेकर पार्टी निर्मित होगी।

5. आम मजदूरों के साथ पार्टी का रिश्ता कायम होना काफी जरूरी है। बगैर इसके मजदूरों की तरक्की नहीं होगी।

6. पार्टी कभी भी 'खवोटिस्ट' यानी पूछल्लावादी पार्टी नहीं बनेगी। समाज में घट रही घटनाओं को अपनी स्वत:स्फूर्तता पर छोड़ कर पार्टी घटना के पीछे-पीछे नहीं चलेगी। लेनिन ने दिखाया था कि ''क्रांतिकारी सिद्धांत के बगैर क्रांतिकारी आंदोलन निर्मित नहीं हो सकता। सबसे उन्नत सिद्धांत द्वारा संचालित होने पर ही कोई पार्टी मजदूर वर्ग के अगुआ दस्ते की भूमिका निभा सकती है। .... स्वत:स्फूर्तता के जो हिमायती हैं, जो चेतना की भूमिका को नजरअन्दाज करते हैं, पार्टी की भूमिका को गौण कर देते हैं, वे इसके जरिये जाने-अनजाने मजदूरों के अंदर बुर्जुआ विचारधारा के प्रभाव को विस्तार करने में ही मदद पहुँचाते हैं''।

'एक कदम आगे दो कदम पीछे' (' One step forward two step back ') नामक प्रसिद्ध पुस्तक में लेनिन ने पहली बार मार्क्सवाद के इतिहास में पार्टी की भूमिका की चर्चा की। उन्होंने दिखाया कि सर्वहारा वर्ग का नेतृत्वकारी संगठन, पार्टी उसका मुख्य हथियार है। इसके बगैर मजदूर वर्ग की कोई भी क्रांति, सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व की स्थापना का संघर्ष असंभव है।

रूस के ज्यादातर सोशल डेमोक्रेटिक संगठनों ने बोल्शेविकों का साथ दिया। उस दौरान कॉमरेड स्तालिन जेल में थे। पार्टी की दूसरी कांग्रेस के फैसलों के बारे में जानकारी होने पर उन्होंने लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविकों को ही अपना समर्थन दिया।

इसके बाद बोल्शेविक मजदूर वर्ग के आंदोलन को संगठित करने के काम में कूद पड़े। 1901 से 1904 के दौरान रूस में आंदोलन की काफी तरक्की हुई। 1904 में रूस-जापान की लड़ाई छिड़ गई। जार सरकार की उम्मीद थी कि यह लड़ाई क्रांतिकारी आंदोलन की प्रगति को रोक देगी। लेकिन उनकी उम्मीदों पर पानी फेरकर बोल्शेविकों ने 1904 के दिसम्बर में बाकू तेल क्षेत्र में एक विशाल हड़ताल संगठित की और इसके प्रभाव में आकर देश भर में हड़तालों का सिलसिला चल पड़ा। ये सारी हड़तालें मानो वज्रनिनाद की तरह देश में आने वाली क्रांति का संदेश दे गयीं।

1905 का पहला क्रांतिकारी उभार

पहले ही कहा जा चुका है कि 1903 में दूसरी कांग्रेस में एक एकीकृत पार्टी का ढाँचा लेकर सोशल डेमाक्रेटिक पार्टी (आरएसडीएलपी) के अविर्भाव के बावजूद पार्टी की स्थिति मानो एक शरीर में दो आत्माओं जैसी थी। लेनिनवादी कार्यकर्ता 'बोल्शेविक' के नाम से और मार्तोव, ट्रॉटस्की आदि नेताओं के अनुयायियों को 'मेंशेविक' के नाम से जाना जाता था। प्लेखानोव पहले तो लेनिन के साथ थे, पर बाद में उनका झुकाव मेंशेविकों की ओर होता गया और एक समय में आकर 'ईस्क्रा' पर 'मेंशेविकों' का कब्जा हो गया।। पार्टी के सांगठनिक नियम-सिद्धांतों के बारे में मेंशेविक अपनी राय 'ईस्क्रा' के जरिये प्रकट करते रहे।

इसी बीच, 'ईस्क्रा' के साथ-साथ पार्टी की केन्द्रीय कमेटी भी बोल्शेविकों के नियंत्रण से बाहर चली गयी। लेकिन, लेनिन की पुस्तक 'एक कदम आगे दो कदम पीछे' ने संगठन संबंधी मेंशेविकों की अवसरवादी धारणाओं को चकनाचूर कर दिया और पार्टी के नेता-कार्यकर्ताओं के बीच एक साफ विभाजन रेखा खींच दी।

ऐसी स्थिति में बोल्शेविक पार्टी की तीसरी कांग्रेस की तैयारी में लगे रहे। 1904 के अगस्त में लेनिन के संचालन में स्विट्जरलैंड में बोल्शेविकों का सम्मेलन आयोजित हुआ। अगले साल की शुरुआत में ही उन्होंने अपना मुखपत्र 'व्येपोंद' (आगे बढ़ो) प्रकाशित किया। इस तरह से सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी दो धड़ों में बँट गयी।

पार्टी के अंदर जब संघर्ष तेज हो रहा था, ठीक उसी समय रूस में जन आंदोलन भी तीव्र हो रहा था। एक तरफ 1904 में आरंभ हुए रूस-जापान के साम्राज्यवादी युद्ध से छुटकारा पाने की ख्वाहिश थी, तो दूसरी तरफ लगातार बढ़ते शोषण में जकड़े किसान-मजदूरों का संघर्ष हिलोरें ले रहा था। 1905 का साल रूस के क्रांतिकारी आंदोलन के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ। साल की शुरूआत में ही जन आंदोलन का उफान पैदा हो गया था। इस दौर की एक खास घटना थी 'रक्तरंजित रविवार'। 9 जनवरी को करीब डेढ़ लाख मजदूर और उनके परिवारजन सेंट पीट्र्सबर्ग में जार के महल के सामने इकट्ठे हुए। इस प्रदर्शन का नेतृत्व पादरी गापन कर रहे थे । चूँकि इस आंदोलन में काफी संख्या में मजदूर शामिल थे, इसलिए आंदोलन का हश्र चाहे जो भी हो, लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक भी इस आंदोलन में शामिल हुए। निहत्थे मजदूरों के इस जमावड़े में जार की सेना द्वारा चलायी गोली से एक हजार लोगों ने अपनी जान गवायीं। हजारों मजदूर घायल और गिरफ्तार हुए। इस खूनी घटना से सारा रूस हिल उठा। हड़ताल, बैरिकेड (मोर्चाबंदी) और प्रतिरोध आंदोलन से पूरे रूस में क्रांति का ज्वार-सा आ गया। पोटम्किन जंगी जहाज के नाविकों और नौसेना की बगावत इस समय की एक उल्लेखनीय घटना थी। आंदोलन को ध्वस्त करने के लिए जार ने तमाम जनता को मताधिकार प्रदान कर 'ड्यूमा' (जार शासित रूसी संसद) के चुनाव का एलान कर दिया। लेकिन बोल्शेविकों ने उस का बहिष्कार कर जन आंदोलन को और आगे बढ़ाने की घोषणा की।

1905 के दिसम्बर महीने में बोल्शेविक पार्टी ने दूसरी ताकतों के साथ मिलकर चौतरफा हथियारबंद बगावत शुरू कर दी। लेकिन जार ने इसके खिलाफ सारी ताकतों को इकट्ठा कर जबर्दस्त हमला बोल कर क्रांति की इस कोशिश को पूरी तरह से नाकाम कर दिया। मेंशेविकों ने 'देशप्रेम' की मानसिकता से जार के युद्ध-प्रयासों को समर्थन दिया और वे उदारवादी बुर्जुआ वर्ग पर पूरी तरह से निर्भरशील रहे। लेकिन लेनिन ने 1905 की रूस की इस बुर्जुआ जनवादी क्रांति को दूसरे रूप में चिह्नित किया। उन्होंने कहा कि यह घटना ऐसे समय में घटित हो रही है जब विश्व पूँजीवाद साम्राज्यवाद के स्तर पर पहुँच गया है। इसलिए उन्होंने जोर देकर कहा, ''इस बुर्जुआ जनवादी क्रांति में सर्वहारा वर्ग ही नेता की भूमिका निभायेगा।''। उनकी राय में जीत हासिल करने के लिए यह क्रांति मजदूर वर्ग के नेतृत्व में संचालित होनी चाहिए। यही वजह है कि बोल्शेविक हथियारबंद बगावत के जरिये जार के शासन का खात्मा कर मजदूर-किसानों के प्रतिनिधियों को लेकर अस्थायी क्रांतिकारी सरकार की स्थापना करना चाहते थे। आम आदमी को हथियारों से लैस करने पर मेंशेविकों की ओर से प्लेखानोव ने जोरदार एतराज जताया। मेंशेविकों के इसी विश्वासघात का फायदा उठाकर निरंकुश जार सरकार ने क्रांतिकारी आंदोलन पर जबर्दस्त हमला बोल दिया। क्रांतिकारी बगावत को वापस ले लिया गया। लेनिन ने कहा, ''1905 से 1907–इन तीन सालों के बहादुराना संघर्ष के जरिये रूस के सर्वहारा वर्ग ने अपने लिए और रूसी जनता के लिए जो सहूलियतें हासिल की हैं, उन्हें हासिल करने में अन्य देशों को कई युग लगे हैं। इस संघर्ष ने विश्वासघातक, घृणित और मरणासन्न उदारतावाद के प्रभाव से मजदूर वर्ग को मुक्त किया है। इसने रूस के तमाम शोषित-पीड़ित लोगों को क्रांतिकारी जन आन्दोलन निर्मित करने की ताकत दी है।'' रूस की

यह पहली क्रांति सफल तो नहीं हुई, पर यह पूरी दुनिया में लोगों के मुक्ति-संग्राम को तेज करने में काफी कारगर साबित हुई।

इस असफल क्रांति ने ही रूस को दुनिया की क्रांति के मुख्य केन्द्र में तब्दील किया और लेनिन की बोल्शेविक पार्टी के नेतृत्व में संचालित रूस का सर्वहारा वर्ग क्रांति के अगुआ दस्ते में तब्दील हुआ। आम जनता की नजरों में रूस के मुख्य सिद्धांतकार, संगठकर्ता और नेता के रूप में लेनिन का अविर्भाव हुआ। लेकिन 1905 की क्रांति की असफलता ने आम आदमी के जेहन में मायूसी भी पैदा की। लेनिन के महान प्रेरणादायी नेतृत्व ने ही जनता को हताशा के चंगुल से आजाद कर सर्वहारा वर्ग के क्रांतिकारी संघर्ष को संगठित करने के लिए उसमें फिर नई जान डाल दी थी। क्रांति को ताकतवर बनाने के एकमात्र मकसद को लेकर क्रांतिकारी संघर्ष को आगे बढ़ाने में संघर्ष का रास्ता काफी ऊबड़-खाबड़ और जटिल था। लेकिन इतनी मुसीबतों के बीच भी लेनिन सही दिशा में आगे बढ़े थे।

इसी बीच अप्रैल महीने में लंदन में पार्टी की तीसरी कांग्रेस आयोजित हुई। मेंशेविकों ने एक साथ कांग्रेस आयोजित करने में अपनी असहमति जताकर अलग सम्मेलन आयोजित किया। इस घटना को लेनिन ने इस रूप में चिह्नित किया कि 'दो कांग्रेस-दो पार्टियां'। मेंशेविकों की भ्रांत और अवसरवादी नीति के जवाब में इसी साल जुलाई में लेनिन की पुस्तक 'जनवादी क्रांति में सोशल डेमोक्रेसी के दो रणकौशल' प्रकाशित हुई।

क्रांति की कोशिश ऊपरी तौर पर नाकाम हो जाने से बोल्शेविकों ने दिसम्बर में नये तरीके से आंदोलन गठित करने की तैयारी शुरू की। आंदोलनकारी मजदूरों के बीच पार्टी की ताकत को बढ़ाने की आवाज उठी। इस दौरान दोनों धड़ों के बीच एकता की बात भी चर्चा का विषय बनी। लेनिन ने इस प्रस्ताव से सहमत होकर मेंशेविकों के समक्ष एकता सम्मेलन का प्रस्ताव रखा। 1906 के अप्रैल महीने में स्वीडन के स्टॉकहोम में 'एकता सम्मेलन' के नाम से मशहूर आरएसडीएलपी की चौथी कांग्रेस आयोजित हुई। नयी केन्द्रीय कमेटी में बोल्शेविकों की संख्या कम थी। हालांकि आगे चलकर इसी एकता के जरिये देश के विस्तृत हिस्सों में विभिन्न क्षेत्रीय संगठनों में मेंशेविकों के साथ जुड़े बहुत सारे होनहार और अच्छे कार्यकर्ताओं व संगठनकर्ताओं को बोल्शेविक विचारधारा के साथ नजदीकी रिश्ता कायम करने का मौका मिला। मेंशेविकों की अवसरवादी मानसिकता उनके समक्ष धीरे-धीरे उजागर होती गई।

इधर जार ने 'दूसरी ड्यूमा' की घोषणा की। बोल्शेविकों ने नये सिरे से जन आंदोलन की ताकत जुटाने के लिए ड्यूमा में शामिल होने का फैसला किया। 1905 की क्रांति असफल होने के चलते जनता में निराशा घर कर गयी थी। ऐसी स्थिति में लेनिन चाहते

(शेष पृष्ठ 6 पर)

महान नवम्बर क्रान्ति.....

(पृष्ठ 5 का शेष)

थे कि क्रांतिकारी लोग ड्यूमा में शिरकत कर जनता के सामने मौजूदा समाज व्यवस्था के निकम्मेपन को उजागर करें। ड्यूमा के संबंध में जनता का मोहभंग हो और वह क्रांति के समर्थन में आगे आये। इसी तरह से लेनिन ने दिखाया कि क्रांतिकारी आंदोलन की जरूरत से दो भिन्न परिस्थितियों में किस तरह से मार्क्सवादियों के फैसले भी भिन्न हो जाते हैं। उन्होंने कहा, ''1905 में बुल्गिन ड्यूमा का बॉयकाट करने का रणकौशल उस परिस्थिति में बिल्कुल सही रणकौशल था। ... वक्त आ गया है, जब क्रांतिकारी सोशल डेमोक्रेटों को निश्चित तौर पर बॉयकाट का रणकौशल छोड़ना होगा। 1906 में जब दूसरी ड्यूमा का गठन किया जायेगा (''अगर'' गठन हुआ तो), तब उसमें शामिल होने में हम भी पीछे नहीं रहेंगे।'' (Collected works, vol 2, P 142-145)। लेनिन ने यह भी दिखाया, ''कभी संसद के अंदर संघर्ष, तो कभी संसद के बाहर संघर्ष, कभी संसद में भागीदारी करना, तो कभी उसका बॉयकाट करने का रणकौशल अपनाना और इस तरह से संघर्ष के विभिन्न रूपों के आपसी संबंध और सम्पर्क-सूत्र, ये सारी बातें खास महत्व की थीं।... 1905 में बोल्शेविकों द्वारा पार्लियामेंट बॉयकाट की घटना ने क्रांतिकारी सर्वहारा वर्ग को अमूल्य राजनैतिक अनुभवों से समृद्ध किया है और दिखाया है कि कानूनी व गैर कानूनी, संसदीय व गैर-संसदीय विभिन्न आंदोलनों को जब संयोजित किया जाता है, तो कभी-कभी आंदोलन के संसदीय रूप का परित्याग करना सिर्फ अच्छा ही नहीं, बल्कि जरूरी भी होता है। लेकिन, इस अनुभव की नकल कर, जाँच-परख किये बगैर दूसरी परिस्थिति में अंधे की तरह प्रयोग करने से महा अनर्थ होगा... । बोल्शेविक सर्वहारा वर्ग की पार्टी के 'कोर' की रक्षा (ताकतवर और उन्नत करना तो दूर रहा) ही नहीं कर पाते, यदि वे कठोर संघर्ष के जरिये इस दृष्टिकोण को बरकरार नहीं रख पाते कि कानूनी और गैर कानूनी, दोनों किस्मों के संघर्ष का संचालन करना जरूरी फर्ज है और यहाँ तक कि घोर प्रतिक्रियावादी पार्लियामेंट में शामिल होना भी जरूरी फर्ज है ''('वामपंथी कम्युनिज्म एक बचकाना मर्ज')।

आज, जब पार्लियामेंट(संसद) के अंदर के आंदोलन के साथ बाहर के आंदोलन को संयोजित करने के मामले में तरह-तरह के सवाल उठ रहे हैं, तो ऐसे में लेनिन की यह सीख काफी महत्वपूर्ण है। जब तक क्रांतिकारी आंदोलन की लहर पूरे देश में नहीं फैल जाती, जब तक बुर्जुआ संसदीय राजनीति सें जनता का मोहभंग नहीं हो जाता, तब तक संसद के बाहर के आंदोलन की आवाज की गूँज को संसद के अंदर पहुँचाने के लिए संसदीय मंच का जहाँ तक हो सके, इस्तेमाल करने की जरूरत रहेगी। पूँजीवादी शोषण से निजात दिलाने के सवाल पर बुर्जुआ संसदीय व्यवस्था बिल्कुल निकम्मी है- संसद में शिरकत करते हुए इस सच्चाई से जनता को अवगत और सचेत किया जा सकता है। क्रांतिकारी विचारधारा से लैस होकर आम जनता जब आर-पार की आखिरी लड़ाई के लिए आगे बढ़ेगी, सिर्फ तभी संसदीय आंदोलन की जरूरत खत्म होगी और संसद का बहिष्कार करने की स्थिति पैदा होगी।

मेंशेविकों ने भी ड्यूमा में शिरकत करने का फैसला लिया। लेकिन उनकी राय में यह फैसला था कि दूसरी संसदीय जनवादी पार्टियों के साथ मिलकर जार की मंशा पूरी करने के लायक एक ड्यूमा निर्मित करो, जन आंदोलन पर लगाम कसो। पार्टी की केन्द्रीय कमेटी में मेंशेविकों का बहुमत रहने के चलते फैसला उनके पक्ष में जाने के आसार थे। समझौतापरस्ती के रुझान से मजदूर वर्ग और जन आंदोलन को बचाने के मकसद से बोल्शेविकों ने पार्टी कांग्रेस बुलाने की मांग की। 1907 के मई महीने में लंदन में पार्टी की पाँचवी कांग्रेस आयोजित हुई। ट्रॉटस्की ने मध्यम-मार्ग पर चलने वाली एक पार्टी बनाने की कोशिश की, लेकिन इसमें उन्हें सफलता नहीं मिली। कांग्रेस में फैसला हुआ कि अब से पार्टी अन्य बुर्जुआ व पेटी बुर्जुआ पार्टियों, संसदीय जनवादियों, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरियों, पॉपुलर सोशलिस्टों आदि ताकतों के खिलाफ जोरदार वैचारिक संघर्ष चलायेगी। इसको बोल्शेविकों की एक विजय के रूप में दिखाते हुए कॉमरेड स्तालिन ने लिखा था, ''क्रांतिकारी सोशल डेमोक्रेसी के परचम तले सारे रूस को अगुआ मजदूरों की एक पार्टी में शामिल करना सम्भव हुआ।'' कांग्रेस आयोजित होने के कुछ दिनों के अंदर ही जार सरकार ने दूसरी ड्यूमा को भंग कर क्रांतिकारियों की बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियाँ शुरू कर दी। 1907 के दिसम्बर महीने में लेनिन किसी तरह से गिरफ्तारी से बच कर विदेश चले गये।

स्टालिपिन की प्रतिक्रिया के दिन

1908-1912 का दौर रूसी क्रांतिकारियों के लिए काफी कठिन था। जार के मंत्री स्टालिपिन ने कई हजार क्रांतिकारियों को फाँसी पर लटका दिया। इस दौर को स्टालिपिन की प्रतिक्रिया ('द स्टालिपिन रिएक्शन') के दौर के रूप में जाना जाता है। इस दौर में यानी 1908 से 1912 तक बोल्शेविकों ने गैर कानूनी पार्टी संगठनों की रक्षा करने और पार्टी को मजबूत करने के लिए जहाँ तक सम्भव था, कानूनी अवसरों के इस्तेमाल का रास्ता अपनाया। लेनिन के शब्दों में, पार्टी ने जारशाही के खिलाफ आमने-सामने के प्रत्यक्ष संघर्ष का रास्ता छोड़कर अप्रत्यक्ष रूप में संघर्ष चलाने का रास्ता अपनाया। हरेक कानूनी अवसर का फायदा उठाने की कोशिश जारी रखी। इस दौर में मेंशेविकों ने काम-काज पूरी तरह से ठप कर दिया। तथाकथित बुद्धिजीवियों का यह कहना फैशन बन गया कि नयी स्थिति में मार्क्सवाद में सुधार-संशोधन लाना होगा। बोग्दानोव, लुनाचारस्की, आदि बुद्धिजीवी मार्क्सवाद को 'और विकसित' करने के नाम पर इस महान सिद्धांत के मजबूत वैचारिक आधार को कमजोर कर रहे थे। इनके खिलाफ संघर्ष करने के बजाय प्लेखानोव सहित अन्य मेंशेविक नेताओं ने संघर्ष का रास्ता छोड़ दिया था। इस हमले के खिलाफ संघर्ष छेड़ कर मार्क्सवाद की समझदारी को वास्तविक तौर पर और विकसित करना लेनिन के लिए यह एक बेहद जरूरी काम हो गया था। इस दौरान लेनिन ने अपनी प्रख्यात पुस्तक 'वस्तुवाद और अनुभवसिद्ध आलोचना' ('Materialism and Empirio Criticism') की रचना की। उन्होंने माख, अवेनेरियस आदि की भाववादी सोच के खिलाफ सफल वैचारिक संघर्ष का संचालन किया। लेनिन ने दिखाया कि क्रांति के ज्वार के दौरान किस तरह से आगे बढ़ना होता है - कम्युनिस्टों को यह सीखना होता है। इसी तरह भाटे के दौरान, जब प्रतिक्रियावादी सोच आगे बढ़ रही होती है, तब कैसे काम करना होता है, किस तरह से पार्टी की हिफाजत करने के साथ-साथ उसे ताकतवर भी बनाना होता है, जो भी कानूनी सहूलियतें मिल रही होती हैं, उनका सर्वोत्तम इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है और जनता के साथ संबंध को और मजबूत कैसे किया जाता है - यह सब कुछ कम्युनिस्टों को अवश्य सीखना होगा। ... '' बोल्शेविकों ने काफी योजनाबद्ध ढंग से पीछे हटने का काम किया था, उनकी सेना का नुकसान भी बहुत कम हुआ था। . .. बोल्शेविक यह काम इसलिए कर पाये कि उन्होंने क्रांतिकारी लफ्फाजी करने वाले लोगों के चरित्र को स्पष्ट तौर पर जनता के सामने उजागर कर दिया था और उन्हें पार्टी से बहिष्कृत कर दिया था। ये लोग समझना ही नहीं चाहते थे कि क्रांतिकारियों को अच्छी तरह से यह सीखना होता है कि कैसे घोर प्रतिक्रियावादी पार्लियामेंट के अंदर कानून से बच कर काम करना पड़ता है, कैसे घोर प्रतिक्रियावादी ट्रेड यूनियनों या इस तरह के अन्य संगठनों में काम करना पड़ता है?''

ऐसी स्थिति में क्रांतिकारी पार्टी को अपने ज्ञान को और उन्नत करना होगा। मेन्शेविक तो नहीं, लेकिन लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक निश्चित तौर पर समझ गये थे कि आने वाले कई सालों के अंदर फिर से क्रांतिकारी आंदोलन का उभार पैदा होगा और इस नये उभार में जनता को शामिल करने की जिम्मेदारी पार्टी की ही होगी। लेनिन ने कहा, ''क्रांति को भी एक अलग-थलग अकेला कार्यक्रम या घटना हरगिज नही समझना चाहिए(जैसा कि नदेज्दिन जैसे लोग सम्भवत: समझते हैं); वह तो एक ऐसा सिलसिला होता है जिसमें कमोबेश जोरदार जन विस्फोट और न्यूनाधिक निश्चल शांति के काल बारी-बारी से आते रहते हैं। यही वजह है कि हमारे पार्टी संगठन की गतिविधियों का प्रधान तत्व, इन गतिविधियों का केन्द्र, एक ऐसा कार्य होना चाहिए जो ज्यादा से ज्यादा जोरदार विस्फोटों के काल में भी सम्भव तथा आवश्यक हो और पूर्ण शांति के काल में भी, यानी उसे राजनीतिक आन्दोलन का ऐसा काम होना चाहिए जो सारे रूस में फैला हो, जो जीवन के तमाम पहलुओं पर रोशनी डाले और जो जनता के ज्यादा से ज्यादा व्यापक हिस्से के बीच हो।'' ('क्या करें' वॉल्यूम-5 पेज-514)। उन्होंने आगे और कहा-''क्रांति शुरू होने पर जो क्रांतिकारी बन जाते हैं, वे सही मायने में क्रांतिकारी नहीं होते। जब प्रतिक्रियावादी ताकतें जबर्दस्त हमला बोलती हैं और जब उदारतावादी व जनवादी लोग सबसे अधिक दुविधा में रहते हैं, उस समय भी, जो क्रांति की विचारधारा और नारा लेकर आगे बढ़ सकते हैं वे ही सही मायने में क्रांतिकारी होते हैं। सही क्रांतिकारी वे होते हैं, जो जनता को क्रांतिकारी तरीके से संघर्ष करना सिखाते हैं और इस शिक्षा का नतीजा क्या होगा, शायद पहले से कोई नहीं बता सकता (अर्थात् भविष्यवाणी नहीं कर सकता)।'' (वॉल्यूम-19 पेज-212)। ''क्रांतिकारी आंदोलन में अगली लहर कब आयेगी—कल, परसों या कई महीनों बाद—यह ऐसी कुछ परिस्थितियों पर निर्भर करता है, जिनका पहले से अनुमान लगाना संभव नहीं होता।'' (वॉल्यूम-8 पेज-139)। उन्होंने दिखाया, ''जन-क्रांति कब होगी, उसे तय नहीं किया जा सकता। ... जो लोग क्रांति की तैयारी कर रहे हैं, जनता पर यदि उनका प्रभाव रहे और अगर वे परिस्थिति का सटीक मूल्यांकन कर सकें, तभी क्रांति का समय तय किया जा सकता है।'' (वॉल्यूम-8, पेज-153)।

इस प्रसंग में लेनिन की एक और सीख याद करना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा था, ''आम तौर पर क्रांति के लिए ठोस परिस्थितियाँ क्या हैं? इस संबंध में नीचे जिक्र किये गये लक्षणों पर ध्यान देने से गलतियाँ नहीं होंगी:

1. जब शासक वर्ग के लिए बिना कोई परिवर्तन किये शासन-कार्य चलाना नामुमकिन हो जाता है, जब उच्च वर्ग के लोगों के अंदर किसी न किसी तरह का संकट पैदा हो जाता है, जब शासक वर्ग की नीति में संकट के चलते ऐसी दरार पैदा हो जाती है, जिससे शोषित-पीड़ित जनता के अंदर क्षोभ और नफरत के प्रगटीकरण का विस्फोट होता है। 'दबे-कुचले लोग पुराने तरीके से और गुजर-बसर करना नहीं चाह रहे हैं'—यही लक्षण क्रांति के लिए पर्याप्त नहीं है। 'उच्च वर्ग के लोग भी पुराने तरीके से गुजर-बसर करने में असमर्थ हो रहे हैं' —इस परिस्थिति का पैदा होना भी क्रांति के लिए जरूरी है।

2. जब शोषित-पीड़ित जनता की दु:ख-तकलीफों और मांगों की मात्रा में अन्य समय के मुकाबले काफी इजाफा हो जाता है।

3. उपरोक्त कारणों से जनता की सक्रियता काफी बढ़ जाती है। 'शांत माहौल' में जो जनता किसी विरोध के बिना खुद को लुटने देती है, वही जनता 'बवन्डर के माहौल' में वक्त के तकाजे के चलते और उच्च वर्ग की कारगुजारियों की वजह से सक्रिय हो जाती है और एक स्वतंत्र ऐतिहासिक भूमिका निभाती है।

वास्तविक स्थिति के इन सारे परिवर्तनों के बगैर आम तौर पर क्रांति का होना असम्भव है। इन सारे वस्तुगत परिवर्तनों के योगफल को ही क्रांतिकारी परिस्थिति कहा जाता है।'' (वॉल्यूम-21,पेज-213)

(अगले अंक में जारी....)

संविदा शाला शिक्षक पात्रता परीक्षा में लागू गलत नियमों के खिलाफ
डीवाईओ ने दिया ज्ञापन

आरोन (म.प्र.): सरकार की जनविराधी नीतियों के खिलाफ नगर में डीवाईओ जनआन्दोलन चला रहा है। उसी क्रम में एसयूसीआई(सी) के मनीष श्रीवास्तव ने कहा कि वर्तमान में म.प्र. प्रशासन द्वारा शाला शिक्षक पात्रता में जो नियम बनाएं हैं वे सरासर गलत हैं। वैसे ही राज्य में बेरोजगारी की कमी नहीं है उस पर महंगाई की मार, कम वेतन में नौकरी के अलावा जो नियम आईएएस की परीक्षा में भी नहीं होते लेकिन वे 500/- प्रतिमाह में काम करने वाले एक शिक्षक की परीक्षा में लादे जा रहे हैं। यह सब आम युवाओं की सहनशीलता से परे है। डीवाईओ के सिद्धान्त कुमार ने इस रोजगार-विरोधी नीति का विरोध करते हुए कहा कि यदि इन नियमों को नहीं बदला गया तो डीवाईओ एक बड़ा आन्दोलन करेगा।

जबलपुर में सभा

28 सितम्बर को शहीद-ए-आजम भगत सिंह की जयन्ती पर एक प्रदर्शनी व सभा का आयोजन कला निकेतन पॉलीटेक्निक महाविद्यालय जबलपुर में किया गया। सभा के मुख्य अतिथि पॉलीटेक्निक के प्राचार्य आरसी पाण्डेय व सभा अध्यक्ष कॉमरेड मुदित भटनागर थे। सभा की शुरूआत कॉ. सुभद्रा विश्वास के कविता पाठ से हुई। छात्रों को सम्बोधित करते हुए कॉ. मुदित ने कहा आज भगत सिंह के चरित्र व जीवन-संघर्ष से प्रेरणा लेनी चाहिए। आज छात्रों व युवाओं पर अन्याय व अत्याचार बढ़ता जा रहा है जिससे लड़ने के लिए हमें संगठित होना होगा। सभा को सोमनाथ ने भी सम्बोधित किया।

सभा का संचालन कॉ. आशीष तिवारी ने किया। सभा में सुनील केवट, रोशन दहिया, निर्देश, सुभाष, दिलीप, ओंकार आदि छात्र व छात्राएं उपस्थित थे।

शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में इन्दौर में डीवाईओ का प्रोग्राम

स्थानीय मूसाखेड़ी रिंग रोड चौराहे पर कम्युटर शिक्षण कक्ष में 5 सितम्बर को शिक्षक दिवस मनाया गया। एसयूसीआई(कम्युनिस्ट) की इन्दौर इंचार्ज कॉ. अर्शी खान व सन्तोष मीना ने अपनी बात रखी। शिक्षक नरेन्द्र जायसवाल को सम्मानित किया गया। प्रोग्राम का संचालन डीवाईओ की इन्दौर इंचार्ज कॉ. सौम्या परमार ने किया। डीवाईओ के इंचार्ज कॉ. भागीरथ ने अब्राहम लिन्कन का पत्र पढ़कर सुनाया। छात्र-छात्राओं के किये जा रहे नैतिक पतन पर चिन्ता व्यक्त करते हुए नैतिकता और मूल्यबोध विकसित करने के लिए क्रान्तिकारियों के जीवन में प्रतिफलित उन्नत मूल्यबोधों, नीति-नैतिकता को आदर्श मानने पर बल दिया। कल्चरल प्रोग्राम में कोचिंग के स्टाफ और छात्र-छात्राओं ने गाने और कविताएं सुनाकर समा बांध दिया।

प्रोग्राम के अन्त में डीएसओ के नगर सचिव संतोष मीना ने सभी का आभार

पानी के निजीकरण के खिलाफ विरोध मार्च

दिल्ली सरकार द्वारा पानी के निजीकरण के खिलाफ पानी-निजीकरण, व्यापारीकरण प्रतिरोध कमेटी की शालीमार बाग इकाई ने 7 अक्टूबर को विरोध मार्च किया जिसमें बड़ी संख्या में क्षेत्र के नागरिक शामिल हुए।

'पानी का निजीकरण-व्यापारीकरण बंद करो', 'पानी जीवन का आधार- बंद करो इसका व्यापार', 'पानी का निजीकरण नहीं चलेगा' आदि नारे लगाते हुए क्षेत्र में विरोध मार्च किया गया और ए.जी. के पार्क में सभा भी हुई। सभा को कमेटी की अध्यक्षा श्रीमती मीनू तलवार के अलावा एसयूसीआई(सी) की पीतमपुरा /शालीमार बाग लोकल कमेटी की इंचार्ज प्रकाश सैनी ने सम्बोधित करते हुए कहा कि कि दिल्ली सरकार पिछले दस वर्षों से विश्व बैंक, योजना आयोग तथा निजी कम्पनियों के आदेश पर पानी का निजीकरण करने का प्रयास कर रही है। हालांकि इस दिशा में कुछ कदम पहले से ही ले लिये गये हैं, परन्तु अब सरकार पानी के सम्पूर्ण निजीकरण के लिए ठोस तथा सुनियोजित उपाय कर रही है। वक्ताओं ने कहा कि इन उपायों का मुख्य जोर "सम्पूर्ण खर्च वसूली" को प्राप्त करने के लिए, पानी के शुल्कों में अत्यधिक बढ़ोतरी का सहारा लेना, अनुदानों का सम्पूर्ण उन्मूलन तथा गरीब जनता को सार्वजनिक नलों तथा टैंकरों द्वारा दी जाने वाली मुफ्त पानी की सप्लाई को खत्म करके कॉर्पोरेट घरानों तथा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को फायदा पहुँचाना है। यह नीति दिल्ली की आम जनता के जीवन पर कहर बरपा देगी। सभा का संचालन करते हुए कमेटी की सचिव श्रीमती नीतु खन्ना ने दिल्ली सरकार द्वारा पानी के निजीकरण की नीति की घोर भर्त्सना की तथा 15 नवम्बर 2011 को होने वाले राज्य स्तरीय सम्मेलन में नागरिकों से बढ़चढ़ कर भाग लेने तथा सम्मेलन को सफल बनाने अपील की।

वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित

सागर : 16 अक्तूबर को चेतना अध्ययन केन्द्र यादव कॉलोनी में एआईडीएसओ की जिला इकाई, सागर (म.प्र.) द्वारा वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसका विषय था '' कक्षा 8 तक पास फेल समाप्त करना एवं उच्च शिक्षा में सेमेस्टर पद्धति अप्रसांगिक तरीके से लागू करना अनुचित है''। प्रतियोगिता के सभी प्रतिभागियों ने पक्ष में बात रखते हुए परीक्षा प्रणाली में इस परिवर्तन को सिरे से नकारते हुए कक्षा आठवीं तक सभी को बेरोक-टोक पास करने का विरोध किया। वक्ताओं ने सेमेस्टर प्रणाली पर असंतोष जाहिर करते हुए कहा कि छात्र किताबी कीड़े एवं परीक्षा के दास बनते जा रहे हैं।

प्रतियोगिता में प्रथम स्थान लेखन अहिरवार, दूसरा स्थान राम सिंह कुशवाहा, तीसरा स्थान सोना कुशवाहा ने प्राप्त किया तथा सांत्वना पुरस्कार रमेश एवं अरविंद पटेल को दिया गया। प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि एआईडीएसओ के पूर्व अखिल भारतीय उपाध्यक्ष डॉ. रामावतार शर्मा ने प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरित किये। प्रतियोगिता का संचालन राजू पटेल ने किया।

पेंशन, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, ट्रेड यूनियन व श्रम अधिकारों व रोजगारों पर हमले के खिलाफ दिल्ली राज्य श्रमिक कन्वेंशन

नई दिल्ली: ऑल इंडिया युनाइटेड ट्रेड यूनियन सेन्टर (एआईयूटीयूसी)की दिल्ली राज्य कमेटी द्वारा 12 अक्तूबर को गाँधी शांति प्रतिष्ठान सभागार में एक दिल्ली राज्य श्रमिक कन्वेंशन का आयोजन किया गया। एस एस नेगी ने कन्वेंशन मे एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें कहा गया कि 1991 में उदारीकरण, निजीकरण और भूमण्डलीकरण की नीति को लागू करने से सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, ट्रेड यूनियन व श्रम अधिकारों तथा रोजगारों पर हमले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। संगठन के दिल्ली राज्य सहसचिव कॉ. मैनेजर चौरसिया ने कन्वेंशन में परिचर्चा पत्र पेश किया जिस पर कन्वेंशन में शामिल हुए ट्रेड यूनियन नेताओं व कार्यकर्ताओं ने अपने विचार रखे।

कन्वेंशन के मुख्य वक्ता थे एआईयूटीयूसी के राष्ट्रीय सचिव मंडल सदस्य अचिन्त्य सिन्हा। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर हमला करते हुए सरकार ने पेंशन योजना को खत्म कर दिया है। इसी तरह से पाँचवें व छठे वेतन आयोग द्वारा 10 लाख से भी अधिक रोजगार के अवसर समाप्त कर दिये गये हैं। ट्रेड यूनियन व श्रम अधिकारों पर हमला करते हुए कई प्रकार के भत्ते खत्म करने, अवकाश घटाने जैसे कदम उठाये जा चुके हैं। अभी धरने प्रदर्शन करने, हड़ताल करने, यहाँ तक कि नियमानुसार कार्य पर भी रोक लगाई जा रही है। यूनियन गठित करने, मान्यता समाप्त करने, दफतरों को छीनने की कार्यवाही भी की जा रही है। इसकी ताजा मिसाल एयर इंडिया व मारुति-सुजूकी प्रबंधन द्वारा उठाये गये तानाशाहीपूर्ण कदम हैं। कन्वेंशन की अध्यक्षता जाने माने ट्रेड यूनियन नेता ए.के. मजूमदार ने की। उन्होंने कहा कि सुपर बाजार को बंद करने, बिजली बोर्ड के निजीकरण करने के बाद अब दिल्ली सरकार दिल्ली जल बोर्ड के निजीकरण का जनविरोधी, कर्मचारी-विरोधी कदम उठाने जा रही है। उन्होंने निजीकरण व ठेकेदारीकरण के खिलाफ आन्दोलन को तेज करने की अपील की।

कन्वेंशन को एआईयूटीयूसी दिल्ली राज्य सचिव कॉ. हरीश त्यागी, दीपक ढोलकिया, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष दीपक कुमार ने भी सम्बोधित किया। इस कन्वेंशन में दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों, स्वायत्त संस्थानों, केन्द्र सरकार के कर्मचारियों तथा असगंठित मजदूरों की यूनियनों ने बड़ी संख्या मे भाग लिया। सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास करके आगे के चरण के आन्दोलन का भी ऐलान किया गया।

मुजफ्फरपुर में जमीन के सवाल पर विचार गोष्ठी

'गांधी स्मृति दर्शन समिति' द्वारा 17, 18, 19 सितम्बर को जमीन को लेकर जहां जहां संघर्ष हो रहा है वहां के लोग और जमीन को लेकर चिंतन-मनन करने वाले बुद्धिजीवी व सामाजिक कार्यकर्ताओं को लेकर तीन दिवसीय विचार गोष्ठी का आयोजन समिति के सत्याग्रह भवन में किया गया। विचार गोष्ठी का विषय था : 1) भूदान के आयने में जमीन का मौजूदा सवाल, 2) भूमि अधिग्रहण का सवाल और 3) विकास बनाम विकास। बिहार के मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत 'खेत बचाओ जीवन बचाओ जन संघर्ष कमिटी' मरवन को भी आमंत्रित किया गया जहां की जनता 'बाल मुकन्द सीमेंट एंड रूफिंग लिमिटेड' द्वारा एस्बेस्टस कारखाना खोलने के खिलाफ पिछले 18 महीने से संघर्षरत है। इस संघर्ष को ऑल इण्डिया कृषक खेतमजदूर संगठन का भी पूरा समर्थन प्राप्त है जिसके राज्य सचिव कॉ. अशोक कुमार सिंह के नेतृत्व में 'खेत बचाओ जीवन बचाओ जन संघर्ष कमिटी' के एक 8 सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल ने इस विचार गोष्ठी में भाग लिया जिसमें कमिटी के संयोजक रामचन्द्र राय, सह संयोजक तारकेश्वर गिरि, सिकंदर सिंह, हरेंद्र महतो, कुमोद राम, जय नारायण सिंह, रामनरेश सिंह सभी कमिटी सदस्य थे।

गोष्ठी में कॉ. अशोक कुमार सिंह व तारकेश्वर गिरि ने ऑल इण्डिया कृषक खेत मजदूर संगठन की ओर से अपने विचार रखे।

दिल्ली राज्य छात्र सम्मेलन.

(पृष्ठ 1 का शेष)

इसके बाद कॉ. प्रशांत कुमार ने पिछले 4 साल की सांगठनिक रिपोर्ट पेश की। इसका अनुमोदन कॉ. आसिफ ने किया। अन्त में कॉ. विनय कुमार द्वारा नई राज्य कमेटी के गठन का प्रस्ताव पेश किया गया जो सर्वसम्मति से पारित हुआ। नई राज्य कमेटी में राज्याध्यक्ष कॉ. भास्करानंद, सचिव कॉ. प्रशांत कुमार, उपाध्यक्ष कॉ. दीपक रंजन, कार्यालय सचिव कॉ. राहुल सरकार, कोषाध्यक्ष कॉ. आसिफ और सचिवमण्डल सदस्य कॉ. रवि कुमार, नीरज व कृष्णेन्दु मुखर्जी चुने गये। इसके अलावा, एक 31 सदस्यीय स्टेट काउंसिल भी गठित की गई। इस सत्र का समापन भाषण कॉ. जुबेर रब्बानी ने दिया।

इसके बाद एआईडीएसओ के संस्थापक, इस युग के महान मार्सवादी चिन्तनकार, हमारे प्रिय नेता, शिक्षक व पथ प्रदर्शक कॉमरेड शिवदास घोष पर रचित गीत गाने के साथ सम्मेलन का समापन हुआ।

R.N.I. No.- 43022/85
P.R.No.-DL(C)-12/1123/2009-2011
Posting at IPMBC on 7–8 and 22–23 of Every Month

पूँजीवादी भूमण्डलीकरण की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ
भूमण्डलीय जन आक्रोश की लहर

पूँजीवादी भूमण्डलीकरण की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ फूट पड़े भूमण्डलीय जन आक्रोश ने विश्वव्यापी आन्दोलन की लहर ने 15 अक्टूबर को अमेरिका सहित दुनिया के 80 से भी ज्यादा देशों में लगभग 950 शहरों को अपनी चपेट में ले लिया। अमेरिका के ''ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट''(वाल स्ट्रीट पर कब्जा करो) आन्दोलन से प्रेरणा पाकर हुए अभूतपूर्व विरोध प्रदर्शनों की गूँज दुनिया भर में सुनाई दी है। देश और दुनिया में जन उभार का नजारा देखने को मिला। कुछ ही महीने पहले मिस्र व ट्युनिसिया में स्वेच्छाचारी शासकों के खिलाफ बगाावत हुई थी। अब एक महीने से ज्यादा अर्से से अमेरीका में हो रहे वॉल स्ट्रीट आन्दोलन से प्रेरित होकर अमेरिका के साथ-साथ, पूरे यूरोप में ही नहीं बल्कि एशिया और अफ्रीका के भी कुछ हिस्सों में पूंजीवादी लूट के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों में हजारों हजार लोग सड़कों पर उतर आये हैं।

अमेरिका में कार्पोरेट घरानों की लूट, सामाजिक-आर्थिक गैर बराबरी और वित्तीय उद्योगों को राहत पैकेज दिये जाने के विरोध में महीने भर से चल रहे ''ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट'' अभियान के तहत हुए अभूतपूर्व विरोध प्रदर्शनों में जन समुद्र उमड़ पड़ा था। अमेरिका के मैनहैटन के ब्रुकलिन ब्रिज से लगभग 700 प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। शहर के वित्तीय जिले से लेकर टाइम्स स्कवेयर पर हुए विशाल विरोध प्रदर्शन से सड़क पर यातायात जाम हो गया था। पुलिस दमन के बावजूद लोग वहाँ लगातार तम्बू डाले बैठे हैं। रोष प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अमेरिका के 99 प्रतिशत लोगों के हितों की बलि चढ़ा कर सरकार एक प्रतिशत धनी कार्पोरेट घरानों को सभी सुविधाएं और बेल आऊट पैकेज देती जा रही है। पूंजीवादी आर्थिक संकट का सारा बोझ लोगों के कन्धों पर डालती जा रही है। देश के मेहनतकश लोग बढ़ते टैक्सों के बोझ तले दबते जा रहे हैं, उनकी नौकरियाँ छिनती जा रही हैं। अखबारों की मानें तो अमेरिका में लगभग 4 करोड़ 62 लाख लोग गरीब हैं। हर छः में से एक व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर कर रहा है। (3.10. 2011 का बंगाली अखबार सकालवेला)। लोगों की लड़ाई शोषणमूलक पूँजीवादी व्यवस्था के खिलाफ है जिसमें पूंजीपति और बहुराष्ट्रीय कार्पोरेट घराने जनता का खून चूसकर मुनाफे के अम्बार लगाते जा रहे हैं। लोगों की जमीनें, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सब कुछ छिनता जा रहा है और निर्मम शोषण-जुल्म जारी है जिससे उनका जीना दूभर होता जा रहा है। रोष प्रदर्शनकारियों के बैनरों पर नारे लिखे हुए थे ''पूँजीपति मुनाफाखोरोंऔर उनके बैंकों को राहत पैकेज दिये गये और लोगों को बेच दिया गया।'' इस लूट-खसोट के खिलाफ लम्बे अर्से से जमा उनका गुस्सा फूट पड़ा है। इस अन्याय के खिलाफ वे निचले स्तर से एकजुट होकर उठ खड़े हुए। वे अपने हकों के लिए आवाज बुलन्द कर रहे हैं।

अमेरिका में गत कुछ सालों से जो महामंदी का आलम दिखाई दे रहा है इसकी वजह कोई व्यक्ति नहीं है बल्कि इस सड़ गल चुकी पूंजीवादी व्यवस्था के अन्तर्निहित नियम की वजह से ही यह तीसरे गहन संकट में फंस चुकी है। इसमें यह संकट असमाधेय है। इस संकट से उबरने के लिए इनके द्वारा अपनाया गया भूमण्डलीकरण, उदारीकरण, निजीकरण, खुला बाजार व्यवस्था सहित कोई नुस्खा काम नहीं आया। पूंजीपति-साम्राज्यवादी भूमण्डलीकरण की इन विनाशकारी नीतियों को दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ही लागू करने पर उतारू थे लेकिन लागू कर नहीं पा रहे थे। वे इन्हें केवल तभी लागू कर पाये जब संशोधनवादी नेतृत्व के भीतरघात के चलते सोवियत यूनियन और विश्व समाजवादी खेमा ढह गया। महान लेनिन ने दिखाया था कि साम्राज्यवाद युद्धों को पैदा करता है। अमेरिकी साम्राज्यवादियों ने इराक, लिबिया, अफगानिस्तान और अफ्रीका को अपना निशाना बनाया, फौजी हमले किये और दूसरे देशों के अन्दरूनी मामलों में दखलअन्दाजी कर रहा है। उनकी आजादी व संप्रभुता को पैरो तले रौंद रहा है। जनता पर टैक्सों का भारी बोझ डालकर उनकी कमर तोड़ रहा है। जबकि लोगों को बम नहीं, बल्कि रोजी-रोटी चाहिए। भारत-अमरीकी रणनीतिक साझेदारी भारतीय पूंजीवाद के बढ़ते साम्राज्यवादी चरित्र की ही द्योतक है।

आर्थिक मंदी के इस संकट का समाधान केवल समाजवाद में ही सम्भव है। पिछली सदी के तीस के दशक में ये सभी पूंजीवादी-साम्राज्यवादी देश जहां जबरदस्त मंदी के संकट से ग्रस्त थे वहीं समाजवादी देश सोवियत यूनियन न केवल इससे अछूता था बल्कि दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा था। बेरोजगारी, गरीबी, गैर-बराबरी पूँजीवाद की ही देन हैं। इनसे छुटकारा समाजवाद में है न कि पूँजीवाद में। सभी मानवीय दुख-तकलीफों की जड़ पूँजीवाद का नाश हो-इसलिए जरूरी है। आन्दोलन के अलावा बचने का लोगों के पास और कोई रास्ता नहीं है। इसलिए पूँजीवाद का खात्मा और समाजवाद कायम होना चाहिए। सर्वहारा अन्तर्राष्ट्रीयतावाद का तकाजा है सभी देशों के मजदूर एक हों। मेहनतकश जनता में एका हो और पूँजीवाद के खिलाफ लड़े। पूँजीवाद-विरोधी मजदूर क्रान्ति के लिए आगे बढ़ें। लोगों को मार्क्सवाद- लेनिनवाद-शिवदास घोष चिन्तनधारा से लैस करने की जरूरत है। सही क्रांतिकारी पार्टी के नेतृत्व में ही आन्दोलन अपनी मंजिल को हासिल कर सकता है। यह बड़ी अच्छी बात है कि कार्पोरेट घरानों के लालच को रोकने के लिए दुनिया के मेहनतकशों ने एक अभूतपूर्व हूँकार भरी है। उनके समर्थन में पूरी दुनिया के मेहनतकश अपनी एकजुटता का इज़हार कर रहे हैं और सड़कों पर उतर आए हैं। वॉल स्ट्रीट आन्दोलन से प्रेरित होकर लोग अमेरिका के न्यूयार्क से लेकर न्यूजीलैण्ड तक, आस्ट्रेलिया के सिडनी से लेकर जर्मनी के बर्लिन तक, स्पेन के मैड्रिड से लेकर ब्रिटेन के लन्दन तक, कनाडा के ओटावा से लेकर दक्षिण अफ्रीका के जोहन्सबर्ग तक, ताइवान, हांगकांग, रोम, इटली और तेल अबीब में भी आन्दोलन की आंधी चल रही है। दिनोंदिन यह आन्दोलन जोर पकड़ता जा रहा है। ऐसे में भारत के मेहनतकश भी मूकदर्शक बने नहीं रह सकते। वॉल स्ट्रीट आन्दोलन को सलाम और समर्थन देते हुए तथा इस आन्दोलन के प्रति एकजुटता का इजहार करते हुए एसयूसीआई(सी) की केन्द्रीय कमेटी ने प्रदेश की राजधानी व प्रमुख शहरों में विशाल विरोध प्रदर्शन संगठित करने का फैसला लिया गया है।

आंगनवाड़ी कर्मियों का
राज्य स्तरीय रोष प्रदर्शन

लखनऊ (उ. प्र.): 9 अक्तूबर को प्रदेश के कोने-कोने से आई लगभग छः हजार आंगनवाड़ी कर्मियों ने आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिका वेलफेयर एसोसियेशन सम्बन्धित एआईयूटीयूसी एवं एईएफआई के बैनर तले लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन पर रोष प्रदर्शन किया। झण्डे-बैनरों से सुसज्जित जुलूस चलने से पहले ही पुलिस द्वारा रोक दिये जाने से वहीं विरोध सभा में तब्दील हो गया। सभा की अध्यक्षता संगठन की प्रदेशाध्यक्ष लता शर्मा ने की। यह सभा आईसीडीएस निदेशक आरुति यादव के सड़क पर आकर नेत्रियों से वार्ता करने और ज्ञापन की सभी माँगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिये जाने पर समाप्त हुई। आंगनवाड़ी कर्मियों ने माँगों की तख्तियाँ हाथों में उठायी हुई थी और जोरदार नारे लगाये। उनकी प्रमुख माँग थी आंगनवाड़ी कर्मियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाये, महंगाई के हिसाब से पोषाहार की लागत राशि बढ़ाई जाये, पक्के आंगनवाड़ी सेन्टर निर्मित किये जायें, आईसीडीएस स्कीम में व्याप्त भ्रष्टाचार खत्म किया जाये, आईसीडीएस स्कीम में पंचायतों/ ठेकेदारों / एनजीओ का हस्तक्षेप बंद किया जाये।

सभा को संगठन की प्रदेश सचिव शशिबाला, सरिता मेनपुरी, इरावती कानपुर, आंगनवाड़ी इम्पलाइज फेडरेशन ऑफ इण्डिया(एईएफआई) की राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष कमलेश चाहल, एआईयूटीयूसी, उ.प्र. अध्यक्ष कॉ. राजबली, एआईयूटीयूसी के राष्ट्रीय सचिव कॉ. अचिंत्य सिन्हा ने सभा को सम्बोधित किया। वक्ताओं ने कहा कि उ.प्र. में सब से ज्यादा, लगभग साढ़े तीन लाख आंगनवाड़ी वर्कर और हैल्पर हैं लेकिन खेद की बात है कि उन्हें देश में सबसे कम मानदेय भत्ता व अन्य सुविधाएं मिलती हैं। आंगनवाड़ी सेन्टरों व पोषाहार का भी बुरा हाल है। उन्होंने आंगनवाड़ी कर्मियों का आह्वान किया कि वे अपनी माँगें पूरी करवाने के लिए एकजूट हों और आन्दोलन तेज करें। बाद में 13 अक्तूबर को आईसीडीएस निदेशक, लखनऊ ने फोन से सूचित किया कि सरकार ने एसोसियेशन से वार्ता के लिए 15 नवम्बर की तारिख तय की है।

पानी के निजीकरण के खिलाफ जन-सम्मेलन

करोल बाग: पानी के निजीकरण-व्यपारीकरण के खिलाफ दिल्ली में लम्बे समय से चल रहे जनआन्दोलनों की कड़ी में खटीक समाज धर्मशाला में करोल बाग इकाई ने 16 अक्टूबर 2011 को एक जन सम्मेलन आयोजित किया। सभा में एसयूसीआई(सी)दिल्ली राज्य सचिव कॉ. प्रताप सामल, कॉ. नरेन्द्र शर्मा, कॉ. रामनिवास व तोमर जी ने पानी के निजीकरण-व्यापारीकरण के खिलाफ जन आन्दोलन मजबूत करने की अपील की। सम्मेलन में एक 14 सदस्यीय जन कमेटी ''पानी-निजीकरण-व्यापारीकरण प्रतिरोध कमेटी'' गठित की गई। इसमें अध्यक्ष सरिता, उपाध्यक्ष शुभा दीक्षित और एस. एस. बख्शी व सचिव कॉ. राहुल सरकार चुने गए। सभा का संचालन कॉ. ऋतम्भरा ने किया।

सोशलिस्ट यूनिटी सेन्टर ऑफ इण्डिया की ओर से कॉ. गिरिजेश्वर सिंह द्वारा 3ए/38, डब्ल्यू.ई.ए., करोल बाग. नई दिल्ली-5 से संपादित व प्रकाशित तथा परम्परा प्रिंटिंग प्रेस, बी-70/83, इण्डस्ट्रियल एरिया, लॉरेंस रोड, दिल्ली-35 से मुद्रित, दूरभाष: 011-25726631, E-mail: sarvaharadrishtikon@yahoo.com